हिन्दी दैनिक

पथ प्रवाह

RNI No.: UTTHIN/2011/39282

हर खबर पर पैनी नजर

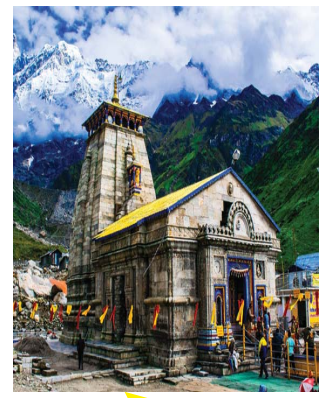

वर्ष:5 अंक:26 पृष्ठ:08 मुल्य:1 रूपये | pathpravah.com | हरिद्वार, शनिवार, 31 जनवरी 2026

सीएम पुष्कर धामी बोले विकसित भारत के सपने को साकार करने में प्रभावी माध्यम प्रगति पोर्टल

पथ प्रवाह, देहरादून

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में भारत सरकार का प्रो-एक्टिव एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन (PRAGATI) पोर्टल एक अहम भूमिका निभा रहा है। वे शुक्रवार को पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) देहरादून द्वारा आयोजित प्रगति पोर्टल विषयक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने बताया कि वर्ष 2015 में शुरू किया गया प्रगति पोर्टल परियोजनाओं, योजनाओं और जन शिकायतों की त्वरित समीक्षा एवं समाधान का एक सशक्त डिजिटल प्लेटफॉर्म है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत लॉन्च इस पोर्टल के माध्यम से केंद्र एवं राज्य सरकारों की प्रमुख योजनाओं की नियमित निगरानी होती है, जिससे विकास कार्यों को गति मिलती है और बाधाओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित होता है।

सीएम धामी ने कहा कि 2014 के बाद देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, परिवहन, रेलवे, आईटी, स्वास्थ्य और हवाई सेवाओं के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। वर्तमान में उत्तराखंड में 3.50 लाख करोड़ रुपये के कुल निवेश वाली 42 बड़ी परियोजनाओं की निगरानी की जा रही है। इनमें से 1.22 लाख करोड़ रुपये की लागत वाले 15 हाई-वैल्यू प्रोजेक्ट्स की समीक्षा सीधे प्रगति मैकेनिज्म के तहत हो रही है। अब तक 10 योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, जबकि 32 परियोजनाओं पर कार्य तीव्र गति से जारी है।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने बताया कि अंडर इम्प्लीमेंटेशन परियोजनाओं में सड़क व राजमार्ग की 19, आईटी/आईटीईएस की 3, ऊर्जा उत्पादन की 3, रेलवे की 2 तथा कृषि, उद्योग-वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, अपशिष्ट एवं जल प्रबंधन की एक-एक परियोजना शामिल है। चारधाम सड़क परियोजना और ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे लाइन को उन्होंने राज्य के लिए ऐतिहासिक बताया। सीएम ने कहा कि यह रेलवे लाइन न केवल पर्यटन और चारधाम यात्रा को सुगम बनाएगी, बल्कि सामरिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। मानसून के दौरान बाधित होने वाले मार्गों का विकल्प बनकर यह परियोजना लोगों की यात्रा को आसान बनाएगी।

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी, धनोल्टी और देहरादून आने वाले पर्यटकों को बड़ा लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने पूंजीगत निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना (SASCI) 2025-26 के अंतर्गत उत्तराखंड को कुल ?1,806.49 करोड़ की सहायता प्रदान की है। उन्होंने इसे 'विकसित उत्तराखंड' के विजन को साकार करने की दिशा में मील का पत्थर बताया।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने 195 करोड़ से अधिक की योजनाओं को दी मंजूरी

पथ प्रवाह, देहरादून

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के समग्र विकास, सड़क सुरक्षा, पेयजल व्यवस्था, आपदा राहत, मुख्यमंत्री घोषणाओं के क्रियान्वयन तथा नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करते हुए लगभग रु. 195 करोड़ की धनराशि जारी करने का अनुमोदन दिया है। मुख्यमंत्री की इन स्वीकृतियों को राज्य में आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण और जनकल्याणकारी योजनाओं को गति देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

सड़क सुरक्षा व सौंग बांध परियोजना के लिए 176.91 करोड़ स्वीकृत

मुख्यमंत्री द्वारा 'पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता' (ङ्गस्ष्टढ्ढ) योजना के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में निर्माणाधीन

सौंग बांध पेयजल परियोजना के अवस्थापना निर्माण कार्यों के लिए रु. 103.80 करोड़ की धनराशि अवमुक्त किए जाने को मंजूरी दी गई है। यह परियोजना देहरादून सहित आसपास के क्षेत्रों में दीर्घकालिक पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने में मील का पत्थर साबित होगी।

इसके साथ ही ङ्गस्ष्टढ्ढ योजना के तहत सड़क सुरक्षा अनुरक्षण मद में रु. 73.11 करोड़ की धनराशि भी स्वीकृत की गई है, जिससे प्रदेश में सड़क सुरक्षा उपायों को और मजबूत किया जा सकेगा।

नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए तकनीकी सशक्तिकरण

मुख्यमंत्री श्री धामी ने राज्य में नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से तकनीकी सुदृढ़ीकरण की योजनाओं को भी स्वीकृति दी है। इसके अंतर्गत सभी जनपदों एवं प्रशिक्षण केंद्रों में वर्चुअल कंप्यूटर लैब की स्थापना के लिए रु. 4.83 करोड़, जबकि फॉरेंसिक वर्कस्टेशन के लिए आवश्यक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एवं सॉल्यूशंस की खरीद हेतु रु. 4.30 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। इससे पुलिस, अभियोजन एवं प्रशिक्षण तंत्र को आधुनिक तकनीक से सशक्त किया जा सकेगा।

धराली आपदा प्रभावितों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से सहायता

जनपद उत्तरकाशी की तहसील भटवाड़ी अंतर्गत ग्राम धराली में 5 अगस्त को आई प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों के लिए मुख्यमंत्री ने संवेदनशील निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री राहत कोष से रु. 6 करोड़ 60 लाख 96 हजार 800 की धनराशि स्वीकृत की है। यह राशि आपदा से क्षतिग्रस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं भवनों के प्रभावितों को राहत प्रदान करने के लिए दी जाएगी।

इसके अतिरिक्त धराली, मुखवा एवं हर्षिल क्षेत्रों में कृषि भूमि को हुई क्षति के लिए 64 प्रभावितों को रु. 6 लाख 72 हजार 24 की अतिरिक्त राहत राशि भी स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार इन सभी स्वीकृतियों से संबंधित शासनादेश जारी कर दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री घोषणाओं के क्रियान्वयन को भी मिली गति

मुख्यमंत्री घोषणाओं से जुड़ी नौ योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए रु. 2.21 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। इनमें जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला अंतर्गत रूपिन रज्जि क्षेत्र में धौला से इस्त्रागाड़-चांगशील पर्यटन मार्ग के मरम्मत कार्य हेतु रु. 43.99 लाख तथा जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के विकासखंड मुनस्यारी में धापा से क्वीरी तक संपर्क मार्ग निर्माण के लिए रु. 54.77 लाख की धनराशि शामिल है। इसके साथ ही जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता में समाज कल्याण विभाग से संबंधित मुख्यमंत्री की विभिन्न घोषणाओं के अंतर्गत सात योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु रु. 1.22 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जनकल्याणकारी कैम्पों के माध्यम से लाखों नागरिकों को मिला सीधा लाभ

पथ प्रवाह, देहरादून

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल एवं दूरदर्शी नेतृत्व में प्रदेशभर में 'जन-जन की सरकार जन-जन के द्वार' अभियान के संचालित जनकल्याणकारी कैम्प आम जनता के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो रहे हैं। शासन द्वारा नागरिकों तक योजनाओं एवं सेवाओं की सीधी पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निरंतर कैम्पों का आयोजन किया जा रहा है।

आज प्रदेश में कुल 21 कैम्प आयोजित किए गए, जिनमें 12,822 नागरिकों ने सहभागिता कर विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ प्राप्त किया। इन कैम्पों के माध्यम से आमजन को एक ही स्थान पर त्वरित समाधान, जानकारी एवं सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। अद्यावधि तक प्रदेश में कुल 525 कैम्प आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें अब तक 4,21,363 नागरिकों ने प्रतिभाग किया है। यह आंकड़े मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जनहितैषी सोच, प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था एवं सुशासन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं।

मुख्यमंत्री श्री धामी ने स्पष्ट किया है कि सरकार का उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। कैम्प आधारित इस व्यवस्था से आम जनता को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं, बल्कि सेवाएं स्वयं उनके द्वार तक पहुंच रही हैं।

प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित ये कैम्प पारदर्शिता, त्वरित सेवा वितरण एवं जनसरोकारों की दिशा में एक सशक्त पहल हैं, जो 'सरकार आपके द्वार' की अवधारणा को साकार कर रहे हैं।

अहिंसा के संदेश के साथ बापू को नमन, गांधी स्मृति में प्रार्थना सभा में शामिल हुए पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित गांधी स्मृति में आयोजित प्रार्थना सभा में भाग लिया। यह प्रार्थना सभा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित की गई थी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी वहां मौजूद स्कूली बच्चों से बातचीत करते भी नजर आए।

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर मेरा शत-शत नमन। पूज्य बापू का हमेशा स्वदेशी पर बल रहा, जो विकसित और आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का भी आधारस्तंभ है। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व देशवासियों को कर्तव्य

पथ पर चलने के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूज्य बापू ने मानवता की रक्षा के लिए हमेशा अहिंसा पर बल दिया। उन्होंने कहा कि अहिंसा में वह शक्ति है, जो बिना हथियार के दुनिया को बदल सकती है। उन्होंने बापू के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा,

'अहिंसा परमो धर्मस्तथाऽहिंसा परन्तपः।
अहिंसा परमं सत्यं यतो धर्मः प्रवर्तते॥

सफाई अभियान में ढिलाई बरते जाने पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जतायी नाराजगी

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित हरिद्वार को स्वच्छ,सुंदर जनपद बनाने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। इसीक्रम में जिलाधिकारी ने शुक्रवार को चल रहे सफाई और सौंदर्यीकरण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने आरएम सिडकुल एवं नगर निगम की टीम के साथ कांवड़ पटरी मार्ग पर निरीक्षण किया।

इस दौरान जिलाधिकारी ने पुल जटवाड़ा से सिंहद्वार कांवड़ पटरी मार्ग के आसपास बेहतर साफ सफाई के साथ ही कही जगह पर बाउंड्री वॉल एवं मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए है उसको भी दुरस्त करने के निर्देश दिए। क्षेत्र में उगी झाड़ियों को संबंधित अधिकारियों को तत्काल काटने के निर्देश दिए। सीएसआर के माध्यम से कांवड़ पटरी मार्ग में पौधारोपण किया जा रहा है, उन्होंने कहा कि कांवड़ पटरी मार्ग एक वैकल्पिक मार्ग भी है जिससे श्रद्धालु हरिद्वार आते है, इस मार्ग को दुरस्त करने एवं सौंदर्यकरण करने के निर्देश दिए ताकि हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं एवं हरिद्वार वासियों को यहां पर आने में साफ और सुंदर वातावरण मिल सके। उन्होंने सिंहद्वार पुल के आसपास अतिक्रमण कर लगाई गई फड़, ठेली और अस्थाई दुकानों को तत्काल हटाने के निर्देश नगर निगम के अधिकारियों को दिए। नगर निगम के अधिकारियों को लगातार इस क्षेत्र की निगरानी के निर्देश दिए, जिससे कोई कोई दुबारा अतिक्रमण न करे। यदि कोई व्यक्ति दोबारा अतिक्रमण करता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

सिंहद्वार से कांवड़ पटरी मार्ग पर सीएसआर के माध्यम से अकम्स कंपनी एवं हीरो कंपनी द्वारा किए जा रहे सफाई अभियान का निरीक्षण कर व्यवस्थाओ का जायजा लिया और एकम्स कंपनी एवं हीरो कंपनी के अधिकारियों को निर्देश दिए कि उनके द्वारा कांवड़ पटरी मार्ग पर जो सफाई एवं सौंदर्यकरण का कार्य किया जा रहा है उसमें तेजी लाए।

नगर निगम क्षेत्रांतर्गत सफाई अभियान में ढिलाई एवं लापरवाही बरते जाने पर नाराज़गी व्यक्त करते हुए सफाई अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस दौरान सिडकुल के आरएम कमल किशोर कफल्टिया, एकम्स कंपनी के जीएम केडी शर्मा,हीरो कंपनी के एचआर हेड पंकज भट्, हरीश नौटियाल सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

एक नजर

राष्ट्रीय लोक अदालत का 14 मार्च को देहरादून में होगा आयोजन

पथ प्रवाह, हरिद्वार। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशन में उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के तत्वाधान में उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, नैनीताल एवं समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा अगामी 14 मार्च, 2026 को प्रातः 10:00 बजे से साय 05:00 बजे तक राज्य के मा. उच्च न्यायालय, समस्त जिला तथा अधीनस्थ न्यायालयों, राज्य के समस्त पारिवारिक न्यायालयों, श्रम न्यायालयों, वाणिज्यिक न्यायालयों, राज्य एवं समस्त जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग तथा ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन (ऐसे मामले जो अभी न्यायालय में दायर नहीं हुये है) एवं न्यायालयों में लम्बित निम्न वादों का निस्तारण किया जायेगा। जिनमें फौजदारी के शमनीय मामले, धारा 138 एनआई एक्ट के मामले, मोटर दुर्घटना दावा मामले, वैवाहिक / कुटुम्ब न्यायालयों के मामले, श्रम सम्बन्धित मामले, भूमि अर्जन के मामले, दीवानी वाद, राजस्व और अन्य सहायक मामले, वेतन, भत्तों एवं सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित मामले, विद्युत एवं जलकर बिलों के मामले, धन वसूली से सम्बन्धित मामले, लंबित आईपीआर मामले, उपभोक्ता मामले, किसी अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष अन्य मामले, मोटर वाहन अधिनियम के तहत शमनीय यातायात चालान, अन्य ऐसे मामले जो शुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो सके, का निस्तारण किया जायेगा। जो भी व्यक्ति अपने वादों, मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित करवाना चाहते हैं, वे सम्बन्धित न्यायालय में किसी भी कार्यदिवस में दिनांक 13 मार्च, 2026 तक स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र देकर अपने वादों को नियत करवाकर, इस अवसर का लाभ उठायें। अधिक जानकारी के लिये कार्यालय, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल अथवा सम्बन्धित जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में सम्पर्क करें।

पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने किया कांवड़ मार्ग का निरीक्षण

पथ प्रवाह, हरिद्वार। शारदीय कांवड़ मेले की तैयारी में पुलिस प्रशासन जुट गया है। तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण करने के लिए शुक्रवार को एसपी सिटी और एडीएम हरिद्वार स्वंय निरीक्षण के लिए निकले। इस दौरान अधिकारियों को दिशा निर्देश दिये। निरीक्षण के दौरान सुरक्षित कांवड़ यात्रा के लिए हरिद्वार पुलिस प्रशासन अलर्ट है। अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान कांवड मार्ग पर पैदल भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पुलिस अधीक्षक नगर अभय सिंह, एडीएम पीआर चौहान के साथ क्षेत्राधिकारी नगर एसएस नेगी व पुलिस प्रशासन की टीम द्वारा शारदीय कांवड़ के संबंध में यह स्थलीय निरीक्षण किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा व सुविधाओं को देखते हुए कमियों को समय से पूर्ण करने हेतु संबंधित विभागो को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी का समापन, प्रतिभागियों ने हरिद्वार का बढ़ाया गौरव

पथ प्रवाह, हरिद्वार। जनपद हरिद्वार में चल रही मुख्यमंत्री चैम्पियनशिप ट्रॉफी 2025 राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का शुक्रवार को समापन हो गया। जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी प्रमोद चंद्र पाण्डे ने बताया कि कुश्ती की 42 वेट कैटेगरी में प्रतियोगिता करायी गयी, जिसमें जनपद हरिद्वार के प्रतिभागियों द्वारा 30 गोल्ड, 2 सिल्वर और 6 ब्राउन्स मेडल प्राप्त किये गए। योगासन के प्रतिभागियों ने 18 गोल्ड एवं 2 सिल्वर मेडल प्राप्त कर जनपद हरिद्वार का गौरव बढ़ाया।

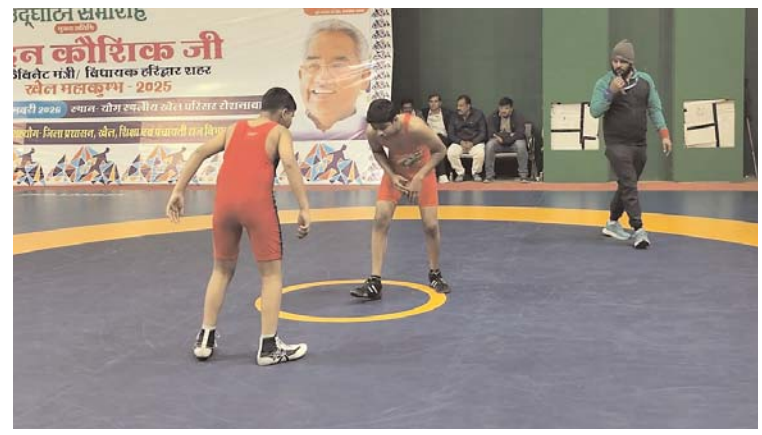

इस अवसर पर उत्तराखंड योगा एसोसिएशन के सचिव रंजीत सिंह, नोड़ल मुख्यमंत्री चैम्पियनशिप ट्रॉफी 2025 राज्य स्तरीय प्रतियोगिता युवा कल्याण विभाग, मुकेश कुमार भट्ट, क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी पौड़ी गढ़वाल पूनम मिश्रा, क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी, बहादराबाद सोनू कुमार, भगवानपुर विक्रान्त चौधरी, प्रशासनिक अधिकारी युवा कल्याण विभाग हरिद्वार जितेन्द्र पुण्ड़ीर, जिला क्रीड़ाधिकारी शबाली गुरूंग, उप क्रीड़ाधिकारी प्रदीप कुमार तथा युवा कल्याण विभाग से खेल प्रशिक्षक मुदस्सीर (समीर) तथा अन्य विभागीय कार्मिक उपस्थित रहे। प्रतियोगिता का सफल संचालन नोडल मुख्यमंत्री चैम्पियनशिप ट्रॉफी हरिद्वार मुकेश कुमार भट्ट द्वारा किया गया।

जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने जनता की सेवा में झोंक दी ताकत, जनसमस्याओं में संजीदा

पथ प्रवाह, उत्तरकाशी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों एवं जिलाधिकारी प्रशांत आर्य के कुशल मार्गदर्शन में जनपद उत्तरकाशी में संचालित 45 दिवसीय विशेष अभियान 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' के अंतर्गत विकासखंड नौगांव की न्याय पंचायत तिया स्थित इंटर कॉलेज कलोगी में भव्य बहुउद्देशीय शिविर एवं जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिविर में श्याम डोभाल, अपर सचिव नवनीत पांडेय तथा उपजिलाधिकारी बड़कोट बृजेश कुमार तिवारी की उपस्थिति में विभागीय अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ प्रदान किया।

शिविर में कुल 28 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 25 शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। शेष जटिल मामलों में संबंधित विभागों को शीघ्र कार्यवाही के निर्देश दिए गए। ग्राम तिया निवासी गुड्डी देवी द्वारा पेयजल समस्या उठाए जाने पर अपर सचिव नवनीत पांडेय ने अधिशासी अभियंता पेयजल निगम को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। धनीराम थपलियाल ने ठाकरा नहर की क्षतिग्रस्त स्थिति के कारण सिंचाई बाधित होने की समस्या रखी, जिस पर सिंचाई खंड पुरोला को तत्काल निरीक्षण के आदेश दिए गए। वहीं सोवन सिंह राणा, ग्राम पालुका ने कुआं-कफनोल मोटर मार्ग पर धारी बाजार में सड़क क्षति की शिकायत की, जिस पर लोनिवि बड़कोट को निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त स्पष्टष्ट सूची संशोधन संबंधी शिकायत पर मुख्य विकास अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए।

शिविर में राजस्व विभाग द्वारा 5 लोगों के आय, जाति, स्थायी एवं हैसियत प्रमाण पत्र बनाए गए। ग्राम्य विकास विभाग ने 3, पंचायतीराज विभाग ने 8 लोगों को योजनाओं की जानकारी दी। कृषि विभाग द्वारा 40 लोगों को कृषि उपकरण वितरित किए गए, जबकि उद्यान विभाग ने 10 लोगों को लाभान्वित किया। उद्योग विभाग ने 11, समाज कल्याण विभाग ने 6, महिला एवं बाल कल्याण विभाग ने 147, सहकारिता विभाग ने 65 लोगों को योजनाओं से जोड़ा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 100 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाइयां वितरित की गईं, आयुष विभाग ने 48 लोगों की जांच की। पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने 92, जबकि कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग ने 50 लोगों को कैरियर काउंसलिंग प्रदान की। क्षेत्रवासियों ने अभियान की सराहना करते हुए कहा कि अब उन्हें छोटी समस्याओं के लिए जिला या तहसील मुख्यालय नहीं जाना पड़ रहा है। शिविर में श्याम डोभाल (प्रभारी, टिहरी लोकसभा), विजय बधानी, संजय थपलियाल, ग्राम प्रधान तिया रीना बहुगुणा, तहसीलदार रेनू सैनी, खंड विकास अधिकारी कैलाश चंद्र रमोला, न्याय पंचायत नोडल अधिकारी डॉ. एच.एस. बिष्ट सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

एक नजर

महंत गोविंद दास के हत्यारोपी ललित की जमानत खारिज

पथ प्रवाह, हरिद्वार। कनखल स्थित भक्ति श्रद्धा आश्रम के महंत गोविंद दास हत्याकांड में न्यायालय ने आरोपी को बड़ा झटका देते हुए उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है। पंचम अपर जिला जज श्री अरुण वोहरा की अदालत ने मामले की सुनवाई के उपरांत हत्यारोपी ललित की जमानत याचिका निरस्त कर दी। शासकीय अधिवक्ता बिरेश चन्द कौशिवा ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले के शिकायतकर्ता रुद्रानन्द द्वारा दिनांक 17 अक्टूबर 2024 को थाना कनखल में महंत गोविंद दास के लापता होने की गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने एक आरोपी रामगोपाल को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में रामगोपाल ने अपने साथियों अशोक, सौरव, प्रदीप और ललित के साथ मिलकर महंत गोविंद दास की संपत्ति और धन हड़पने के लालच में हत्या करने का खुलासा किया। अभियोजन के अनुसार आरोपियों ने महंत गोविंद दास के भोजन में नशीली गोलियां मिलाईं, नशे का इंजेक्शन लगाया तथा गला दबाकर उनकी निर्मम हत्या की। इसके बाद महंत की बैंक चेकबुक और लगभग 30 लाख रुपये की एफडी चोरी करने का भी आरोप है। हत्याकांड को अंजाम देने के पश्चात सभी आरोपियों ने मिलकर महंत के शव को कट्टे में बांधकर नदी में फेंक दिया। मामले की गंभीरता, आरोपों की प्रकृति और प्रस्तुत साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए विचारण न्यायालय ने ललित पुत्र दिनेश शर्मा, निवासी करनाल (हरियाणा) की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

दो मिनिट का मौन रखकर स्वतंत्रता संग्राम बलिदानियों को किया याद

पथ प्रवाह, हरिद्वार। शासन के निर्देशों के क्रम में भारत के स्वतन्त्रता संग्राम में अपने जीवन का बलिदान देने वाले शहीदों की स्मृति में कलेक्ट्रेट परिसर में अपर जिलाधिकारी सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने 02 मिनट का मौन धारण कर शहीदों को नमन कर याद किया। अपर जिलाधिकारी राजस्व एवं वित्त दीपेंद्र सिंह नेगी,जिला स्तरीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में शुक्रवार को भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जीवन का बलिदान देने वाले शहीदों का स्मरण करते हुए 11 बजे सभी कार्य और गतिविधियां रोककर सायरन बजाकर दो मिनिट का मौन धारण और नमन कर याद किया गया। इस दौरान सयुक्त निर्देशक विधि श्याम सिंह तोमर,डीजीसी रेवेन्यू विजयपाल सिंह,मुख्य प्रशासनिक अधिकारी आशीष वर्मा,प्रशासनिक अधिकारी नवीन मोहन सहित कलेक्ट्रेट के आधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

महिला ऐच्छिक ब्यूरो का सार्थक प्रयास, काउंसलिंग में तीन परिवारों को टूटने से बचाया

पथ प्रवाह, हरिद्वार। रिजर्व पुलिस लाईन रोशनाबाद हरिद्वार में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद हरिद्वार प्रमेन्द्र सिंह डोबाल के दिशा-निर्देशन में पुलिस उच्चाधिकारीगण की देखरेख में बिखरते परिवारों को जोडने के लिए महिला एच्छिक ब्यूरो की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में महिला हेल्पलाइन रुड़की में प्रचलित जटिल पारिवारिक विवादों व दोनों पक्षों को आमने सामने बैठाकर बैठक में उपस्थित सभी लोगों द्वारा काउंसलिंग की गई। काउंसलिंग से तीन परिवारों को टूटने से बचाया गया। इस दौरान 2 प्रकरणों में सोचने समझने के लिए अग्रिम तिथि दी गई। हरिद्वार पुलिस सभी से आग्रह करती है परिवार एक जीने की पाठशाला है जिसमें हमें छोटी-छोटी बातों को दरकिनार कर एक दूसरे के दुख दर्द को समझकर उसका निराकरण निकालना चाहिए ना की उसमें कमियां निकालनी चाहिए। परिवार है तो हम एक समाज का अंग है। बैठक में मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर अरूण कुमार, समाजशास्त्री विनोद शर्मा, अधिवक्ता रीमा साहीम, समाज सेविका रंजना शर्मा (प्रधानाचार्य), प्रभारी महिला हेल्पलाइन रुड़की उपनिरीक्षक ममता मखलोगा, महिला कांस्टेबल ममता व निर्मला द्वारा प्रतिभाग किया गया।

पुलिस ने स्कूल में दी बच्चों को सुरक्षा संबंधी जानकारी

पथ प्रवाह, हरिद्वार। पुलिस आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आरएनआई में जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनपद हरिद्वार पुलिस द्वारा 26 जनवरी से यह अभियान चलाया जा रहा है। अभियान 31 जनवरी तक चलाया जाएगा। चलाये जा रहे जागरुकता अभियान पुलिस आपके द्वार कार्यक्रम के अन्तर्गत कोतवाली भगवानपुर पुलिस टीम द्वारा आरएनआई में महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा से संबंधित विभिन्न कानूनों, आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112, महिला हेल्पलाइन 1090/1091 साइबर अपराध से बचाव, छेड़छाड़, घरेलू हिंसा तथा किसी भी आपात स्थिति में त्वरित सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

बहुउद्देशीय शिविरों के आयोजन की नई तारीख तय, उठा सकेंगी जनता लाभ

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार डॉ. ललित नारायण मिश्र ने बताया कि जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' अभियान के अंतर्गत बीती 22 जनवरी को विकास खण्ड भगवानपुर के न्याय पचायत डाडा जलालपुर में किसान इन्टर कॉलेज वहबलपुर हसोबाला में अपर जिलाधिकारी प्रशासन हरिद्वार की अध्यक्षता में एवं 23 जनवरी को विकास खण्ड रूडकी की न्याय पंचायत-खजरपुर में पंचायत भवन, टोडा कल्याणपुर (अ0) में अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में बहुउद्?देशीय शिविर आयोजित किया जाना था। दिनांक 22 जनवरी 2026 को अपर जिलाधिकारी प्रशासन हरिद्वार की वीआईपी कार्यक्रम में ड्यूटी लगने एवं दिनांक 23 जनवरी 2026 को बसन्त पंचमी का स्थानीय अवकाश घोषित होने के कारण उक्त स्थानों एवं तिथियों पर आयोजित होने वाले जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' अभियान के अंतर्गत बहुउद्देशीय शिविर क्रमशः दिनांक 04 फरवरी, 2026 (बुधवार)को अपर जिलाधिकारी प्रशासन हरिद्वार की अध्यक्षता में प्रातः 10 बजे से आयोजित किया जायेगा। जिसमें मुख्य पशु चिकित्साधिकारी हरिद्वार को न्याय पंचायत नोडल अधिकारी नामित किया गया है, एवं 05 फरवरी 2026 (गुरुवार)को मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार की अध्यक्षता में प्रातः 10 बजे से आयोजित किया जायेगा, जिसमें खण्ड विकास अधिकारी रुड़की को न्याय पंचायत नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

इसी तरह 27 जनवरी 2026 को विकास खण्ड बहादराबाद के न्याय पंचायत जमालपुर कला में सामूदायिक भवन जमालपुर कला में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), हरिद्वार की अध्यक्षता में एवं 28 जनवरी 2026 को विकास खण्ड भगवानपुर की न्याय पंचायत भलस्वागाज में पंचायत भवन, भेडकी सैदाबाद में अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में बहुउ?देशीय शिविर आयोजित किया जाना था। दिनांक 27 जनवरी 2026 को यूसीसी दिवस मनाये जाने एवं दिनांक 28 जनवरी 2026 को विकास खण्ड भगवानपुर में उप-चुनाव होने के कारण 27 जनवरी 2026 आयोजित होने वाला बहुउद्देशीय शिविर अपर जिलाधिकारी हरिद्वार (प्रशासन) की अध्यक्षता में दिनांक 07 फरवरी 2026 को प्रातः 10 बजे से आयोजित किया जायेगा, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) हरिद्वार को न्याय पंचायत नोडल अधिकारी नामित किया गया है। एवं 28 जनवरी 2026 आयोजित होने वाला बहुउद्देशीय शिविर मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार की अध्यक्षता में दिनांक 07 फरवरी 2026 को प्रातः 10 बजे से आयोजित किया जायेगा, जिसमें सहायक गन्ना आयुक्त हरिद्वार को न्याय पंचायत नोडल अधिकारी नामित किया गया है। उक्त तिथि को आयोजित होने वाले बहुउद्देशीय शिविर में प्रतिभाग करते हुए आयोजित स्थलों पर विभागों द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जनमानस हेतु सम्बन्धित विभागीय स्टॉल भी लगाये जाएंगे।

1562 लोगों को मिला बहुउद्देशीय शिविर में योजनाओं का लाभ

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

मुख्य विकास अधिकारी डॉ ललित नारायण मिश्र की अध्यक्षता में विकास खंड नारसन के न्याय पंचायत मखदूमपुर राजकीय इंटर कॉलेज मखदूमपुर में जन-जन की सरकार जन-जन के द्वार अभियान के अंतर्गत बहुउद्देशीय शिविर आयोजन किया गया। बहुउद्देशीय शिविर में 189 लोगों को विभिन्न विभागों से प्रमाण पत्र निर्गत किए गए तथा 313 लोगों विभिन्न विभागों की संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया। इस शिविर में 1049 लोगों ने प्रतिभाग किया।

बहुउद्देशीय शिविर में कुल 31 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 24 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष शिकायतों के निस्तारण हेतु संबंधित विभागों को आवश्यक आदेश जारी कर दिए गए। उपाध्यक्ष, समाज कल्याण योजनाएं अनुश्रवण समिति (राज्यमंत्री स्तर) देशराज कर्णवाल ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जन-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र नागरिकों तक पहुँचाना है तथा उनकी समस्याओं का त्वरित गति से समाधान सुनिश्चित करना है। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष रुड़की डॉ मधु, उप जिलाधिकारी अनिल शुक्ला, खंड विकास अधिकारी नारसन सुभाष सैनी सहित समस्त ग्राम प्रधानगण,पंचायत सदस्यगण,अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। विकास खण्ड लक्सर में उप जिलाधिकारी लक्सर सौरभ असवाल की अध्यक्षता में न्याय पंचायत मुंडाखेड़ा कलां के पंचायत घर खंडजा कुतुबपुर में शिविर का आयोजन किया गया। विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित जन कल्याणकारी योजनों से 1249 क्षेत्रवासियों को लाभान्वित किया गया। तथा विभिन्न विभागों के माध्यम से 1450 लोगों को विभिन्न प्रमाण पत्र निर्गत किए गए,इस शिविर में 3860 लोगों द्वारा किया गया प्रतिभाग। आयोजित शिविर ने क्षेत्रवासियों द्वारा विभिन्न विभागों से संबंधित 66 समस्याएं दर्ज कराई गई,जिसमें 61 समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया,शेष समस्याओं को त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित विभागों को प्रेषित किया गया।

जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक में उठा घाटों पर अतिक्रमण और नालों से गंगा में जा रहे गंदे पानी का मुद्दा

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

जिला गंगा संरक्षण समिति की 69 वीं बैठक शुक्रवार को जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने जल संस्थान हरिद्वार एवं पेय जल निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने विभाग द्वारा संचालित एस.टी.पी की नियमित रूप से मॉनीटरिंग करें। इस दौरान उन्होंने कहा कि 14 एम.एल.डी. एस.टी.पी सराय एवं 33 एम.एल.डी. एस.टी.पी सलियर की सम्बधित फर्म पर अपने स्तर से कार्यवाही कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। नगर निगम के अधिकारियों को जनपद हरिद्वार में संचालित गौशालाओं, डेयरी के लिये डेयरी वॉयलाज बनाने के साथ ही नालियों में भूसा व गोबर डालने वालों पर चालानी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने नगर निगम हरिद्वार को निर्देशित करते हुए कहा कि कस्साबान नाले का माह में दो बार औचक निरीक्षण कर किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि पाये जाने पर एनजीटी के निर्देशों के अनुसार अधिकतम जुर्माना लगाने एवं दुकानों के आवंटन की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर लिया जाए। उन्होंने पुलिस, नगर निगम, सिंचाई विभाग यूपी और हरिद्वार को विभिन्न गंगा घाटों एवं नालों जिनमें चमकादड़ टापू, दूधियाबंध व दक्षिण काली माता मन्दिर के आस पास हुए अतिक्रमण को चिन्हित करते हुए हटाने के निर्देश दिए साथ ही हरकी पौड़ी क्षेत्रांतर्गत विभिन पुलों पर किए गए अतिक्रमण को हटा कर इस क्षेत्र की निरंतर निगरानी करने के निर्देश दिए, जिससे कि कोई फिर से पुलों पर अतिक्रमण न करे। नगर निगम एवं सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये है कि गंगा को स्वच्छ एवं निर्मल रखने के लिए किसी भी दशा में गंगा में किसी भी नालों गंदा पानी एवं कूड़ा कचरा न जाये, इसके साथ ही उचित प्रबन्धन करने के निर्देश दिये गये। नगर निगम द्वारा बताया गया कि हरिद्वार क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर साइन/सूचना बोर्ड लगा रखे है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र, अपर जिलाधिकारी दीपेंद्र सिंह नेगी, एसीपी जितेंद्र चौधरी, सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी, उप प्रभागीय अधिकरी पूनम कैथूरा, एसडीओ उत्तरप्रदेश कैनाल भारत भूषण, अधीक्षण अभियंता जल संस्थान हरीश बंसल, एसएनए नगर निगम ऋषभ उनियाल, जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी मीरा रावत, समिति के सदस्य रामेश्वर गौड़, मनोज निषाद, एडवोकेट हिमांशु सरीन, अधिशासी अभियंता लोनिवि दीपक कुमार एवं सम्बन्धित अधिकारी मौजूद रहे।

संपादकीय

देश की आर्थिक दिशा और जनआकांक्षाओं का बजट

लोकसभा का बजट सत्र इस समय चल रहा है और इसके साथ ही देश की आर्थिक नीतियों, विकास प्राथमिकताओं और सामाजिक दायित्वों पर गंभीर मंथन हो रहा है। यह सत्र केवल आय-व्यय के आंकड़ों तक सीमित नहीं होता, बल्कि सरकार की सोच, नीति और भविष्य की रूपरेखा को स्पष्ट करता है।

बजट सत्र के दौरान सरकार द्वारा प्रस्तुत आम बजट से किसान, युवा, मध्यम वर्ग, उद्योग, व्यापारी और गरीब तबके को बड़ी उम्मीदें रहती हैं। महंगाई नियंत्रण, रोजगार सृजन, कृषि आय में वृद्धि, शिक्षा-स्वास्थ्य में सुधार और बुनियादी ढांचे का विस्तार ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। लोकसभा में होने वाली चर्चा इन विषयों को दिशा देने का काम करती है।

वर्तमान बजट सत्र में विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को केंद्र में रखकर इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल अर्थव्यवस्था, हरित ऊर्जा, रेलवे, सड़क और रक्षा क्षेत्र में निवेश पर विशेष फोकस दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने की प्रतिबद्धता भी सरकार के एजेंडे में शामिल है।

लोकसभा में विपक्ष की भूमिका इस सत्र में और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। बजट पर सार्थक बहस, तथ्यों के साथ उठाए गए सवाल और वैकल्पिक सुझाव लोकतंत्र को मजबूती देते हैं। यदि चर्चा मुद्दों पर केंद्रित रहती है, तो यह सत्र जनता के हित में ठोस नतीजे देने में सक्षम होता है। वहीं अनावश्यक हंगामा और व्यवधान न केवल संसद का समय नष्ट करते हैं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों को भी कमजोर करते हैं।

आज देश की जनता बजट से केवल घोषणाएं नहीं, बल्कि जवाबदेही और परिणाम चाहती है। वह यह जानना चाहती है कि बजट प्रावधानों का प्रभाव रोजगार, महंगाई और जीवन स्तर पर कैसे पड़ेगा। ऐसे में लोकसभा का बजट सत्र सरकार के लिए अपनी नीतियों को स्पष्ट करने और जनता का भरोसा मजबूत करने का महत्वपूर्ण अवसर है।

लोकसभा का बजट सत्र केवल वित्तीय प्रक्रिया नहीं, बल्कि देश के भविष्य को दिशा देने वाला निर्णायक मंच है। इस सत्र से निकलने वाले निर्णय आने वाले वर्षों में भारत की विकास यात्रा को गति देंगे–यही इसकी सबसे बड़ी सार्थकता है।

सरकारी सेवा: निर्लज्ज आचरण के नए कीर्तिमान

चैतन्य भट्ट

टीवी चैनलों की बहसों और रियलिटी शोज में रोने धोने का ड्रामा अब सरकारी सेवाओं में भी पैर पसारने लगा है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या से डिप्टी जीएसटी कमिश्नर प्रशांत कुमार ने सरकार के समर्थन में अपनी सरकारी नौकरी से स्तीफा दे दिया है। हिलक हिलक कर आंसू बहाते हुए उनका एक वीडियो वायरल है। संदर्भ व्यक्तिगत परेशानी, जातिगत भेदभाव या नौकरी में पक्षपात का नहीं है। बकौल प्रशांत कुमार यह कदम उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ , प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के ख़िलाफ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बयान के कारण उठाया है। उनका कहना है कि वह इन नेताओं पर अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा लगाए गए आरोपों से बेहद आहत है और इसलिए राज्य सरकार के समर्थन में सरकारी सेवा से त्यागपत्र दे रहे हैं।

इस्तीफे के बाद प्रशांत कुमार पर उनके सगे बड़े भाई डॉ. विश्वजीत सिंह ने फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने का आरोप लगाया है। उनके मुताबिक, प्रशांत कुमार को फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट के जरिए सरकारी नौकरी मिली थी। इस संबंध में वर्ष 2021 में दर्ज शिकायत के बाद मंडलीय चिकित्सा परिषद ने प्रशांत सिंह को मेडिकल बोर्ड के सामने जांच के लिए बुलाया, लेकिन वे पेश नहीं हुए। प्रशांत कुमार प्रशासनिक अधिकारी बनने से पहले राजनीतिक पारी भी खेल चुके हैं। वर्ष 2011 में वह अमर सिंह की पार्टी लोकमंच के जिलाध्यक्ष थे। कभी अमर सिंह के करीबी माने जाने वाले प्रशांत कुमार 2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट के लिए भी प्रयासरत रहे, हालांकि सफलता नहीं मिली।

इसके पहले यूपी पीसीएस 2019 बैच के अधिकारी और बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री भी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद को ब्राह्मणों के अपमान से जोड़ते हुए नौकरी से इस्तीफा देकर राजनैतिक और प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचा चुके हैं। यूजीसी की नई गाइडलाइन की तुलना रालेट एक्ट से करते हुए उसे भी अपने इस्तीफे का कारण बताया है। अग्निहोत्री के अनुसार उनका इस्तीफ़ा पद और प्रतिष्ठा से ऊपर स्वधर्म और स्वाभिमान है व्यक्तिगत लाभ या हानि नहीं, बल्कि समाज के प्रति उनकी जवाबदेही और अंतरात्मा की आवाज से प्रेरित है।? अग्निहोत्री ने सवर्ण वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वैकल्पिक राजनीतिक व्यवस्था बनाने का राग भी अलापा है। नवीनतम जानकारी के अनुसार अग्निहोत्री को इस इस्तीफा प्रकरण में तत्काल निलंबन रूपी तथाकथित दंड दिया गया है।

सरकारी सेवकों द्वारा राजनीतिक दल या विचार धारा विशेष के प्रति पूर्वाग्रह का मामला नया नहीं है। नागरिक होने के नाते किसी भी व्यक्ति की अपनी राजनीतिक विचारधारा और दृष्टिकोण हो सकते हैं, लेकिन कार्यपालिका पदाधिकारी के रूप में, उनसे निष्पक्ष रूप से व्यापक देश और जनहित में काम करने की अपेक्षा रहती है। सरकारी सेवा के लिए निर्धारित आचरण नियम हैं जिनके अनुसार राजनीतिक दल और विचारधारा के लिए प्रतिबद्धता वर्जित है। यह मूल्य अब बिखर रहे हैं और नौकरशाही पार्टी और नेता विशेष के लिए खुलेआम प्रतिबद्ध नजर आती है। राजनीतिक दल तो छोड़िए, नेता विशेष के सत्ताधीन होते ही प्रशासनिक कसावट के नाम पर चहेते अधिकारियों की पोस्टिंग के मामले सबने देखे हैं। नौकरी छोड़कर चुनाव लड़ने के भी कितने ही उदाहरण हैं। ऐसे भी संदर्भ हैं जहां सरकारी सेवक ने नौकरी छोड़ी, चुनाव लड़ा और असफल होने पर पुनः मजे से नौकरी में वापस आ गया। सेवानिवृत्ति के बाद बड़े अफसरों की शीर्ष संवैधानिक और अन्य संस्थाओं में ताजपोशी अब स्वीकृत व्यवस्था है। इनमें वे संस्थान भी शामिल हैं जहां विषय विशेषज्ञ की जरूरत होती है। सरकारी सेवा संविधान और व्यापक जनहित के लिए काम करने के बजाय व्यक्तिगत लाभ पूरे करने का साधन बन गई है। हालांकि हमाम में सारे ही निर्वस्त्र नहीं है। ऐसे सरकारी सेवक भी हैं जिनके लिए अभी भी सेवा के मूलभूत संवैधानिक सिद्धांत ही सर्वोपरि हैं। मगर अल्पमत में होने का दंश है कि कुछ करने नहीं देता।

बहरहाल सरकार के समर्थन या विरोध में खुले आम सरकारी नौकरी से स्तीफा देने की यह नई बानगियां बताती हैं कि राजनीतिक बेशर्मी नित नए कीर्तिमान रचने पर उतारू है। सरकारी सेवा की मूल भावना के अनुसार नौकरी बिना किसी पूर्वाग्रह के सिर्फ और सिर्फ संविधान के प्रति जवाबदेही और व्यापक जनहित के लिए ही की जानी चाहिए। इसके लिए बाकायदा शपथ भी ली जाती है। यह प्रकरण दर्शाते हैं कि इस भावना और शपथ की हैसियत रद्दी कागज के टुकड़े जितनी ही रह गई है। निष्पक्ष और गैर-राजनीतिक होना सरकारी सेवाओं के मूलभूत मूल्यों में से एक है। सरकारी सेवक राजनीतिक रूप से तटस्थ रहने और विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं वाली निर्वाचित सरकारों के प्रति समान प्रतिबद्धता के साथ निष्पक्ष रूप से जनसेवा के लिए बाध्य हैं।

31 जनवरी को प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय ज़ेब्रा दिवस

धारीदार संदेश : ज़ेब्रा दिवस और वन्यजीव संरक्षण की पुकार

सुनील कुमार महला

(इंटरनेशनल ज़ेब्रा डे) मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य ज़ेब्रा जैसे दुर्लभ, सुंदर और उपयोगी वन्य जीव के संरक्षण के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। आज तेज़ी से बढ़ते शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, खेती और बस्तियों के विस्तार के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई, अवैध शिकार, जलवायु परिवर्तन तथा पानी की बढ़ती कमी के कारण ज़ेब्रा के प्राकृतिक आवास लगातार नष्ट हो रहे हैं। इसका सीधा परिणाम यह है कि ज़ेब्रा की आबादी में तेज़ गिरावट दर्ज की जा रही है।

पाठकों को बताता चलूं कि ज़ेब्रा केवल एक आकर्षक जीव नहीं, बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। इन्हें पारिस्थितिकी तंत्र का इंजीनियर कहा जाता है, क्योंकि ये घास के मैदानों को संतुलित और स्वस्थ बनाए रखते हैं। ज़ेब्रा लंबी और सख्त घास को खाते हैं, जिससे नीचे से कोमल घास उगती है, जिसे विल्डेबीस्ट जैसे अन्य शाकाहारी जीव खाते हैं। इस तरह ज़ेब्रा अनेक प्रजातियों के जीवन को अप्रत्यक्ष रूप से सहारा देते हैं। सूखे के समय ये पानी के स्रोत खोज लेते हैं, जिससे अन्य जानवरों को भी लाभ होता है।ज़ेब्रा, घोड़े और गधों के परिवार इक्वस से संबंध रखते हैं, फिर भी इन्हें कभी पालतू नहीं बनाया जा सका। इसका कारण इनका स्वभाव है-ज़ेब्रा अत्यधिक डरपोक होने के साथ-साथ बेहद आक्रामक भी होते हैं। अफ्रीका के खुले मैदानों में शेरों और तेंदुओं जैसे शिकारी जीवों के बीच रहने के कारण इनमें आत्मरक्षा की प्रवृत्ति अत्यंत तीव्र होती है। इनकी लात (किक) इतनी शक्तिशाली होती है कि वह शेर का जबड़ा तक तोड़ सकती है। यही कारण है कि ज़ेब्रा किसी को अपनी पीठ पर बैठने नहीं देते।

ज़ेब्रा का शरीर मूल रूप से काला माना जाता है, जिस पर सफेद धारियाँ होती हैं। भ्रूण अवस्था में ज़ेब्रा पूरी तरह काला होता है; विकास के दौरान सफेद धारियाँ बाद में उभरती हैं। ये धारियाँ केवल सौंदर्य का कारण नहीं, बल्कि प्रकृति की एक अद्भुत वैज्ञानिक रचना हैं। ज़ेब्रा की धारियाँ शरीर के लिए प्राकृतिक एसी का काम करती हैं। दरअसल, इनकी काली धारियाँ गर्मी को सोखती हैं, जबकि सफेद धारियाँ उसे परावर्तित करती हैं। इससे त्वचा के ऊपर हवा की सूक्ष्म लहरें बनती हैं, जो अफ्रीका की भीषण गर्मी में शरीर को ठंडा रखने में मदद करती हैं।इसके अलावा ज़ेब्रा की धारियाँ एक प्राकृतिक बारकोड हैं। दुनिया में किसी भी दो ज़ेब्रा की धारियाँ एक जैसी नहीं होतीं-बिल्कुल इंसानों की उंगलियों के निशानों की तरह। ज़ेब्रा परिवार के सदस्य एक-दूसरे को इन्हीं पैटर्न्स के माध्यम से पहचानते हैं। यही धारियाँ मक्खियों और परजीवी कीटों से भी रक्षा करती हैं। शोध बताते हैं कि ज़ेब्रा की धारियाँ मक्खियों की आँखों को भ्रमित कर देती हैं, जिसे 'मोशन डैज़ल' कहा जाता है, और वे ज़ेब्रा पर ठीक से बैठ नहीं पातीं। यह एक प्रभावी प्राकृतिक कीट-रक्षक है। जब ज़ेब्रा का पूरा झुंड एक साथ दौड़ता है, तो उनकी धारियाँ मिलकर एक बड़ा, हिलता-डुलता दृश्य बना देती हैं, जिससे शेर जैसे शिकारी यह तय नहीं कर पाते कि एक ज़ेब्रा कहाँ शुरू होता है और कहाँ समाप्त। यही भ्रम ज़ेब्रा की जान बचाता है। ज़ेब्रा लगभग 65 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लंबे समय तक दौड़ सकते हैं और जिग-जैग मोशन में भागकर शिकारियों को धोखा देते हैं।

ज़ेब्रा झुंड में रहना पसंद करते हैं, जिसे 'डैज़ल' या 'ज़ील' कहा जाता है। झुंड में चलते समय सामान्यतः नर ज़ेब्रा आगे रहता है और मादाएँ उसके पीछे। यदि कोई ज़ेब्रा घायल हो जाए, तो पूरा झुंड उसकी रक्षा के लिए एकजुट हो जाता है। ज़ेब्रा और शुतुरमुर्ग अथवा विल्डेबीस्ट के बीच गहरी दोस्ती देखने को मिलती है। शुतुरमुर्ग दूर तक देख सकता है, जबकि ज़ेब्रा की सूंघने और सुनने की शक्ति अधिक विकसित होती है।इस प्रकार ये एक-दूसरे को खतरे की सूचना देकर बचाते हैं। जानकारी मिलती है कि ज़ेब्रा की इंद्रियाँ अत्यंत विकसित होती हैं। इनकी नाइट विज़न गजब की होती है। ये खड़े-खड़े भी सो सकते हैं और सोते समय भी इनके कान चारों दिशाओं में घूमते रहते हैं। ज़ेब्रा कानों और पूँछ की स्थिति के माध्यम से संवाद करते हैं। ये रंग पहचान सकते हैं, हालांकि ऑरेंज रंग नहीं देख पाते। ज़ेब्रा घोड़ों की तरह हिनहिनाते नहीं; उनकी आवाज़ गधे और कुत्ते के भौंकने का मिश्रण होती है, जिसे क्वा-हा जैसी ध्वनि से जोड़ा जाता है।

ज़ेब्रा के शिशु जन्म के मात्र 6 मिनट में खड़े, 10 मिनट में चलने और लगभग 20 मिनट में दौड़ने लगते हैं। शिशु लगभग एक वर्ष तक माँ का दूध पीते हैं। मादा ज़ेब्रा अपने बच्चों की रक्षा के लिए अत्यंत साहसी होती है। हालांकि, ज़ेब्रा पेड़ों पर नहीं चढ़ते, लेकिन माउंटेन ज़ेब्रा चट्टानी पहाड़ों पर चढ़ने में माहिर होते हैं। उनके नुकीले और सख्त खुर उन्हें खड़ी ढलानों पर भी वैसी ही पकड़ देते हैं जैसी किसी पेशेवर पर्वतारोही के जूतों को मिलती है। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि घोड़े और ज़ेब्रा एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि ज़ेब्रा कुछ ऐसे वायरस के वाहक होते हैं जिनका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन वही वायरस घोड़ों के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं।

वास्तव में,ज़ेब्रा किसी एक प्रजाति का नाम नहीं, बल्कि इक्वस वंश की तीन प्रमुख प्रजातियों का सामूहिक नाम है-मैदानी ज़ेब्रा, पर्वतीय ज़ेब्रा और ग्रेवीज़ ज़ेब्रा। ये मुख्य रूप से अफ्रीका के घास के मैदानों और खुले जंगलों में पाए जाते हैं, जिनमें केन्या, तंज़ानिया, इथियोपिया, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना और ज़िम्बाब्वे शामिल हैं। यदि हम यहां पर ज़ेब्रा की जनसंख्या आंकड़ों की बात करें तो 2026 के हालिया वन्यजीव गणना के अनुसार, दुनिया में कुल मिलाकर लगभग 5.5 लाख से 6 लाख ज़ेब्रा बचे हैं।मैदानी ज़ेब्रा सबसे आम प्रजाति है, जिनकी अनुमानित संख्या लगभग 5 लाख है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में शिकार और आवास की कमी के कारण इनकी संख्या में लगभग 25% गिरावट आई है और इन्हें संकट के करीब श्रेणी में रखा गया है।पर्वतीय ज़ेब्रा मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया में पाए जाते हैं। इनकी संख्या लगभग 35,000 है। संरक्षण प्रयासों से इनकी स्थिति में सुधार हो रहा है, फिर भी इन्हें अतिसंवेदनशील माना जाता है। इनमें केप माउंटेन ज़ेब्रा की संख्या मात्र 1,500 के आसपास है। वहीं ग्रेवीज़ ज़ेब्रा सबसे दुर्लभ, सबसे बड़ा और सबसे अधिक संकटग्रस्त है। इसका वजन लगभग 1,000 पाउंड तक होता है। यह केवल केन्या और इथियोपिया के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। 1970 के दशक में इनकी संख्या लगभग 15,000 थी, जो अब घटकर मात्र 2,500 से 2,800 रह गई है। इसे आइयूसीएन ने गंभीर रूप से संकटग्रस्त सूची में शामिल किया है। यह भी उल्लेखनीय है कि इस प्रजाति का नाम 19वीं सदी के फ्रांसीसी राष्ट्रपति जूल्स ग्रेवी के नाम पर रखा गया था।अंततः, अंतरराष्ट्रीय ज़ेब्रा दिवस हमें यह स्मरण कराता है कि ज़ेब्रा की घटती संख्या केवल एक प्रजाति का संकट नहीं, बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का संकेत है। ज़ेब्रा का संरक्षण हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है, क्योंकि यदि आज हम सजग नहीं हुए, तो आने वाला कल हमें कभी माफ़ नहीं करेगा।

हर दौर में प्रासंगिक रहेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी

भूपेश गुप्ता

पुण्यतिथि-शहीद दिवस पर आदरांजलि

30 जनवरी भारतीय इतिहास की वह अमर तारीख है, जो आते ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की याद दिला देती है। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में प्रार्थना सभा के मार्ग पर, नाथूराम गोडसे की गोली ने गांधी के शरीर को तो समाप्त कर दिया, पर उनके विचारों को नहीं। भारत इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाते हुए उस महामानव को श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिसने सत्य, अहिंसा और नैतिक साहस को राजनीति की सबसे बड़ी शक्ति बनाया।

2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी ने अपने जीवन के छह दशक संघर्षों में तपकर 'महात्मा' का स्वरूप पाया। उनका सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने आज़ादी की लड़ाई को केवल सत्ता परिवर्तन का आंदोलन नहीं रहने दिया, बल्कि उसे जन-जन का नैतिक आंदोलन बना दिया। जिस ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता, उसे गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह के बल पर झुकने को मजबूर कर दिया।

आज जब विश्व तीसरे विश्वयुद्ध की आशंकाओं से घिरा दिखाई देता है, तब गांधी और अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध की लंबी त्रासदी हो या इज़राइल-फिलिस्तीन के बीच गाज़ा में मानवता को झकझोरता रक्तपात हो, इन सबने दुनिया के विवेक को चुनौती दी है। शक्तिशाली राष्ट्र हथियारों, व्यापार-युद्ध और वैश्विक राजनीतिक दबावों के माध्यम से छोटे देशों पर अपनी शर्तें थोपने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। परिणामस्वरूप करोड़ों लोग विस्थापित हैं, जीवन असुरक्षित है और मानवीय संवेदनाएँ लगातार कमजोर पड़ रही हैं।

इतिहास बताता है कि पिछली सदी ने दो महायुद्धों की विनाशलीला देखी। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले आज भी सभ्यता पर लगा वह दाग हैं जो मानवता को भयभीत कर देते हैं। विज्ञान के विकास के साथ विनाश की क्षमता भी बढ़ी और यही मानव इतिहास का सबसे बड़ा विरोधाभास है। ऐसे दौर में गांधी का संदेश एक चेतावनी भी है और एक समाधान भी। उन्होंने कहा था - जीत वह नहीं जिसमें शत्रु पर विजय हो–जीत वह है जिसमें हिंसा पर विजय हो।

गांधी का सत्याग्रह केवल सिद्धांत नहीं था, वह एक व्यावहारिक रणनीति भी थी। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने नस्लभेद और अपमान के विरुद्ध भारतीयों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। 1903 में 'इंडियन ओपिनियन' जैसे समाचार पत्र के माध्यम से उन्होंने अंग्रेज सत्ता को अभिव्यक्ति की खुली चुनौती दी। बैरिस्टर के रूप में वहां पहुँचे गांधी ने 1894 से 1914 तक सत्याग्रह को जन-आंदोलन का रूप दिया और दुनिया को दिखा दिया कि अन्याय के विरुद्ध सबसे बड़ी शक्ति नैतिकता है। गोपालकृष्ण गोखले जी के आग्रह पर गांधी 1915 में भारत लौटे। उन्होंने तीन वर्षों तक देश का भ्रमण कर भारतीय समाज की नब्ज़ को पहचाना। 1917 में चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों के पक्ष में उनका सत्याग्रह ब्रिटिश शासन के लिए पहली बड़ी चुनौती बना। इसके बाद खेड़ा किसान आंदोलन और अहमदाबाद मिल मज़दूर आंदोलन के माध्यम से गांधी ने प्रमाणित कर दिया कि स्वतंत्रता आंदोलन केवल राजनीतिक वर्ग का विषय नहीं बल्कि वह किसान, मजदूर, स्त्री, दलित और गरीब की साझा आकांक्षा है।

गांधी ने सादगी को शक्ति बना दिया। उन्होंने सूट-बूट त्यागकर धोती धारण की, आश्रम जीवन अपनाया और स्वयं को आमजनता के समान बनाया। उन्होंने चरखा और खादी को केवल वस्त्र नहीं रहने दिया, बल्कि उसे स्वावलंबन और आत्मसम्मान का प्रतीक बना दिया। छुआछूत के विरुद्ध उन्होंने व्यापक जनजागरण किया और 'हरिजन' जैसे शब्दों के माध्यम से समाज को आत्ममंथन के लिए बाध्य किया। उनका अहिंसा-सिद्धांत कितना दृढ़ था, इसका उदाहरण चौरी-चौरा है। जब आंदोलन के दौरान हिंसा हुई तो उन्होंने एक बड़े जनांदोलन को वापस लेने का कठोर निर्णय किया। क्योंकि उनके लिए साधन और लक्ष्य दोनों पवित्र थे। 1942 के 'भारत छोड़ो आंदोलन' में 'करो या मरो' का आह्वान करके उन्होंने ब्रिटिश शासन की अंतिम नींव हिला दी। जेल, यातनाएँ और दबाव, इनमें से कुछ भी उन्हें उनके मूल सिद्धांतों से नहीं डिगा सका। दुर्भाग्य यह रहा कि स्वतंत्रता के बाद देश साम्प्रदायिक विष से अछूता नहीं रह पाया। 1905 के बंगाल विभाजन से बोया गया विभाजन का बीज अंततः 1947 में देश के बंटवारे के रूप में सामने आया।

सीएम पुष्कर धामी की पारदर्शी नीति का असर: खनन राजस्व चार गुना बढ़ा

पथ प्रवाह, देहरादून।

खनन को लेकर आमतौर पर नकारात्मक धारणा के बीच उत्तराखंड ने एक नया उदाहरण पेश किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा लागू की गई पारदर्शी और सख्त खनन नीतियों का सीधा असर यह हुआ कि डेढ़ साल से भी कम समय में राज्य का वार्षिक खनन राजस्व चार गुना से अधिक बढ़ गया। सितंबर 2024 से पहले जहां उत्तराखंड को खनन से लगभग 300 करोड़ रुपये का ही वार्षिक राजस्व प्राप्त हो पाता था, वहीं अब यह आंकड़ा 1200 करोड़ रुपये के पार पहुंच चुका है। राज्य सरकार ने सितंबर 2024 में नई खनन नीति लागू कर खनन आवंटन और परिवहन प्रणाली में व्यापक सुधार किए। इस नीति के तहत खनन लॉट का आवंटन ई-नीलामी के माध्यम से किया गया, जिससे प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनी और

किसी भी प्रकार की अनियमितता पर प्रभावी अंकुश लगा। इसके साथ ही खनन गतिविधियों की सेटेलाइट निगरानी, डिजिटल ट्रैकिंग और माइनिंग सर्विलांस सिस्टम लागू किया गया, जिससे खनन से लेकर परिवहन तक प्रत्येक चरण पर सख्त निगरानी संभव हो सकी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अवैध खनन को राज्य के लिए गंभीर चुनौती मानते हुए पुलिस और प्रशासन को सख्त कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश दिए। इसके परिणामस्वरूप अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगी और राजस्व में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई। सरकार के इन प्रयासों से खनन को लेकर बनी नकारात्मक अवधारणा भी तेजी से बदली है और अब इसे नियंत्रित, पारदर्शी और पर्यावरण-संवेदनशील गतिविधि के रूप में देखा जाने लगा है। खनन क्षेत्र में किए गए इन सुधारों के चलते उत्तराखंड को देशभर में खनन सुधार लागू करने वाले राज्यों में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इस उपलब्धि के फलस्वरूप केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 'पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना (SASCI)' के अंतर्गत उत्तराखंड को ?200 करोड़ की विशेष सहायता स्वीकृत की है। यह सहायता राज्य में आधारभूत संरचना और विकास परियोजनाओं को नई गति देने में सहायक सिद्ध होगी। नई खनन नीति के तहत किए गए प्रमुख सुधारों में ई-नीलामी के माध्यम से खनन लॉट का आवंटन, अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण, खनन परिवहन के लिए माइनिंग सर्विलांस सिस्टम, तथा खनन गतिविधियों की डिजिटल ट्रैकिंग और नियमित निरीक्षण शामिल हैं। इन उपायों से न केवल राजस्व में वृद्धि हुई है, बल्कि पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप खनन को भी सुनिश्चित किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आम लोगों को आवासीय एवं अन्य निर्माण कार्यों तथा विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए खनन सामग्री की आवश्यकता होती है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि खनन पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप हो और इसके लिए एक पारदर्शी एवं जवाबदेह तंत्र विकसित किया गया है। इसके सकारात्मक परिणाम अब स्पष्ट रूप से सामने आ रहे हैं। खनन से प्राप्त बढ़ा हुआ राजस्व राज्य की जनकल्याणकारी योजनाओं को नई रफ्तार दे रहा है और विकास की दिशा में उत्तराखंड को और मजबूत बना रहा है।

सचिवालय में आधुनिक कार्यालय भवन निर्माण ने पकड़ी रफ्तार

पथ प्रवाह, देहरादून

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन को धरातल पर उतारने की दिशा में आवास विभाग पूरी गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। राज्य संपत्ति विभाग की जिम्मेदारी संभालने के बाद से ही आवास सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार विभागीय योजनाओं और निर्माण कार्यों की सतत समीक्षा कर रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को उन्होंने सचिवालय परिसर स्थित निर्माणाधीन आधुनिक कार्यालय भवन का औचक निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान आवास सचिव के साथ एस.एस. रावत (संयुक्त सचिव, राज्य संपत्ति), नीरज कुमार त्रिपाठी (अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग), संदीप वर्मा (अपर सहायक अभियंता, सिविल), गोविंद सिंह (सहायक अभियंता, विद्युत) सहित निर्माण एजेंसी के ठेकेदार शिव कुमार अग्रवाल मौजूद रहे। सचिव ने निर्माण की गुणवत्ता, समय-सीमा और तकनीकी मानकों की विस्तार से समीक्षा करते हुए दो टूक शब्दों में कहा कि निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या गुणवत्ता से समझौता किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रशासनिक ढांचे को आधुनिक और सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सचिवालय परिसर में बन रहा यह आधुनिक कार्यालय भवन इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भविष्य में सरकारी कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी, सुव्यवस्थित और

नागरिक-अनुकूल बनाएगा।

तेजी से आगे बढ़ रहा निर्माण कार्य

राज्य संपत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन सचिवालय परिसर, देहरादून में विश्वकर्मा भवन के समीप 6 मंजिला (जी+5 तथा एक बेसमेंट सहित) आधुनिक कार्यालय भवन का निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है। इस परियोजना को 26 मार्च 2025 को शासनादेश के माध्यम से स्वीकृति प्रदान की गई थी। भवन निर्माण की कुल स्वीकृत लागत 5934.71 लाख है, जिसमें सिविल निर्माण एवं विद्युतीकरण कार्य शामिल हैं। अब तक लगभग 1400 लाख की धनराशि का आवंटन किया जा चुका है।

समय-सीमा और निर्माण एजेंसी

भवन के सिविल निर्माण कार्य का अनुबंध मैसर्स शिव कुमार अग्रवाल को दिया गया है। परियोजना को डेढ़ वर्ष की अवधि में पूर्ण किया जाना है, जिसकी अंतिम तिथि 24 जनवरी 2027 निर्धारित की गई है। सचिव ने निर्देश दिए कि तय समय-सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण करना सर्वोच्च प्राथमिकता रहे।

भवन की आधुनिक विशेषताएं

34म74 मीटर के प्लॉट पर निर्मित हो रहे इस भवन का कुल क्षेत्रफल 2516 वर्ग मीटर है। सभी मंजिलों को मिलाकर कुल निर्मित क्षेत्रफल लगभग 1,04,480 वर्ग फीट होगा। बेसमेंट में 25 कार पार्किंग और 100 दोपहिया वाहन पार्किंग की सुविधा विकसित की जा रही है, जिससे सचिवालय परिसर की पार्किंग समस्या को काफी हद तक राहत मिलेगी। ग्राउंड फ्लोर पर एसबीआई बैंक, पोस्ट ऑफिस, प्रवेश लॉबी और वेटिंग एरिया की सुविधा होगी, जबकि ऊपरी मंजिलों पर सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अनुसचिव स्तर के अधिकारियों के कार्यालय, स्टाफ कक्ष, मीटिंग हॉल और वेटिंग लॉबी विकसित की जा रही हैं।

वर्तमान प्रगति स्थिति

निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति के अनुसार भवन का फाउंडेशन एवं बेसमेंट का सिविल कार्य पूर्ण किया जा चुका है। ग्राउंड फ्लोर का कार्य प्रगति पर है, जिसे 10 फरवरी 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल परियोजना की भौतिक प्रगति लगभग 15 प्रतिशत है। राज्य संपत्ति विभाग द्वारा निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी की जा रही है।

गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं

निरीक्षण के दौरान आवास सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि यह आधुनिक कार्यालय भवन राज्य की प्रशासनिक क्षमता को नई मजबूती देगा। मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप निर्माण कार्यों को समयबद्ध, पारदर्शी और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करना सरकार की प्राथमिकता है।

नियमित निरीक्षण और सतत निगरानी के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप आगे बढ़ें। उन्होंने विश्वास जताया कि यह भवन भविष्य में बेहतर कार्यसंस्कृति और सुगम प्रशासन की मजबूत नींव बनेगा।

रूद्रपुर व पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज जिला चिकित्सालय विभाग को सौंपे

पथ प्रवाह, देहरादून

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में शासन ने राजकीय मेडिकल कॉलेज रूद्रपुर एवं पिथौरागढ़ के सुचारु और प्रभावी संचालन की दिशा में बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है। इसके तहत दोनों जनपदों के प्रमुख जिला चिकित्सालयों को चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड के अधीन हस्तांतरित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री सचिन कुर्वे द्वारा इस संबंध में कार्यालय ज्ञाप जारी करते हुए बताया गया कि पं. रामसुमेर शुक्ल राजकीय मेडिकल कॉलेज, रूद्रपुर के संचालन हेतु जवाहरलाल नेहरू जिला चिकित्सालय रूद्रपुर तथा राजकीय मेडिकल कॉलेज, पिथौरागढ़ के संचालन के लिए बी.डी. पाण्डेय जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ एवं महिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ को विधिवत रूप से चिकित्सा शिक्षा विभाग को सौंपा जा रहा है। उल्लेखनीय है कि ये सभी चिकित्सालय अब तक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के नियंत्रणाधीन थे।

शासन द्वारा जारी आदेशों के अनुसार हस्तांतरण के पश्चात संबंधित चिकित्सालयों का प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण संबंधित मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य/निदेशक के अधीन रहेगा। इससे मेडिकल कॉलेजों के शैक्षणिक, चिकित्सकीय एवं प्रशिक्षण संबंधी कार्यों में बेहतर समन्वय स्थापित होगा और छात्र-छात्राओं को एम.सी.आई. (अब एन.एम.सी.) के मानकों के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

इन चिकित्सालयों में एम.सी.आई. के मानकानुसार अवशेष वांछित उपकरणों एवं औषधियों की व्यवस्था चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। वहीं, चिकित्सालयों में वर्तमान में कार्यरत कार्मिकों के वेतन का भुगतान आगामी एक वर्ष की अवधि तक पूर्ववत व्यवस्था के अंतर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा किया जाएगा। एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने के उपरांत इन सभी चिकित्सा इकाइयों का विधिवत संचालन पूर्ण रूप से चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा। शासन के इस निर्णय को प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे कुमाऊं और तराई क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के साथ-साथ मेडिकल शिक्षा को भी नई गति मिलेगी।

सात लाख की अवैध शराब के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, लोडर वाहन सीज

पथ प्रवाह, देहरादून।

मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड के 'ड्रग्स फ्री देवभूमि' के विजन को धरातल पर उतारने की दिशा में दून पुलिस द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून अजय सिंह के निर्देशों के क्रम में अवैध शराब तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान का असर एक बार फिर देखने को मिला है। दून पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ तीन शराब तस्करों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है।

थाना डोईवाला पुलिस टीम ने 30 जनवरी 2026 को चेकिंग अभियान के दौरान मुखबिर की सूचना पर चौकी क्षेत्र हर्रावाला में एक संदिग्ध लोडर वाहन संख्या UK-07-TD-0190 को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान वाहन में सवार तीन अभियुक्तों के कब्जे से कुल 143 पेटी अवैध शराब बरामद की गई, जिसमें 128 पेटी देशी शराब एवं 15 पेटी अंग्रेजी शराब शामिल हैं। पुलिस द्वारा मौके पर अभियुक्तों से शराब के परिवहन संबंधी वैध दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वे कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं कर सके। इस पर पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार कर लिया तथा तस्करी में प्रयुक्त लोडर वाहन को सीज कर दिया।

इस संबंध में कोतवाली डोईवाला पर

मु0अ0सं0- 26/2026, धारा 60/72 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। बरामद की गई शराब की अनुमानित कीमत करीब 07 लाख रुपये बताई जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:

अनिकेत पुत्र विजय, निवासी 50-बी डांडीपुर मोहल्ला, कोतवाली नगर, देहरादून, मोनू कुमार पुत्र सत्य प्रकाश, निवासी ग्राम बसेड़ा, थाना नौगांवा सादात, जनपद मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, सौरभ जयसवाल पुत्र श्री राजेन्द्र जयसवाल, निवासी चंद्रलोक कॉलोनी, बेहट रोड, कोतवाली देहात, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, हाल निवासी हर्रावाला, देहरादून

बरामदगी का विवरण:

माल्टा ट्रेटा पैक देशी शराब - 128 पेटी, मैकडावल अंग्रेजी शराब - 05 पेटी, इम्पीरियल ब्लू - 08 पेटी, रॉयल स्टेज - 02 पेटी, लोडर वाहन संख्या - च-07-ज्ञ्छ-0190

पुलिस टीम में शामिल:

उप निरीक्षक प्रेम सिंह बिष्ट, हेड कांस्टेबल भूपेन्द्र सिंह, कांस्टेबल सत्यवीर सिंह, कांस्टेबल सुरेन्द्र सिंह

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की सोच और आईजी रिद्धिम अग्रवाल की निगरानी में बदला कुमाऊँ पुलिस का चेहरा

पथ प्रवाह, नैनीताल।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में शासन की प्राथमिकता अब केवल योजनाओं के क्रियान्वयन तक सीमित नहीं रही, बल्कि उनके ठोस और संवेदनशील ज़मीनी असर पर केंद्रित हो गई है। इसी दूरदर्शी सोच का सशक्त उदाहरण कुमाऊँ परिक्षेत्र में देखने को मिल रहा है, जहाँ पुलिसिंग का चेहरा भय से भरोसे की ओर बदलता दिखाई दे रहा है। कुमाऊँ परिक्षेत्र की पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) रिद्धिम अग्रवाल के नेतृत्व में डायल 112 जैसी आपातकालीन सेवा को अब केवल 'रिस्पॉन्स सिस्टम' नहीं, बल्कि 'पीड़ित-संतुष्टि आधारित सेवा' के रूप में विकसित किया गया है। स्पष्ट निर्देश हैं कि तेज़ रिस्पॉन्स ही नहीं, बल्कि पीड़ित की वास्तविक संतुष्टि ही पुलिस कार्रवाई की असली कसौटी होगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विज़न है कि शासन की सफलता योजनाओं की संख्या से नहीं, बल्कि जनता के अनुभव और भरोसे से तय होती है। इसी सोच के अनुरूप पुलिस व्यवस्था को कानून-व्यवस्था से आगे बढ़ाकर जन-सेवा, संवेदनशीलता और संवैधानिक

उत्तरदायित्व से जोड़ा गया है। कुमाऊँ में डायल 112 की बदली हुई कार्यप्रणाली इसी विज़न का जीवंत उदाहरण बनकर सामने आई है।

हर सूचना पर बनेगा 'रिपोर्ट कार्ड'

आईजी रिद्धिम अग्रवाल के निर्देशों पर अब कुमाऊँ में हर पुलिस सूचना की सघन मॉनिटरिंग की जा रही है। कोई भी नागरिक पुलिस को सूचना देता है तो उस पर क्या कार्रवाई हुई, कितनी देर में हुई और पीड़ित कितना संतुष्ट है–इन सभी बिंदुओं की समीक्षा की जाएगी। सूचना मिलने के बावजूद लापरवाही या टालमटोल पाए जाने पर संबंधित पुलिसकर्मी के विरुद्ध कार्रवाई तय मानी जाएगी। इससे एक ओर जहाँ जनता का भरोसा खाकी पर और मजबूत होगा, वहीं दूसरी ओर पुलिस को हर सूचना पर ठोस परिणाम देना अनिवार्य होगा।

डायल 112 : अब आपातकालीन नंबर नहीं, जनता का भरोसा

कुमाऊँ परिक्षेत्र में डायल 112 सेवा अब महज़ कॉल 'निस्तारण' तक सीमित नहीं है। हर गंभीर कॉल के बाद वरिष्ठ स्तर पर समीक्षा, कार्रवाई के उपरांत पीड़ित से सीधा फीडबैक और लापरवाही पाए जाने पर तत्काल जवाबदेही तय की जा रही है। महिला, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता सर्वोपरि रखते हुए शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई गई है।

गंभीर मामलों पर विशेष निगरानी

आईजी रिद्धिम अग्रवाल के निर्देशों पर सितंबर से 31 दिसंबर 2025 तक हत्या, महिला अपराध, लूट, एससी/एसटी, मानव तस्करी, स्नैचिंग और वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े मामलों में विशेष फीडबैक सिस्टम लागू किया गया। इन चार महीनों में कुल 3432 गंभीर कॉल दर्ज की गईं, जिनमें महिला अपराध से संबंधित 3016, मानव तस्करी 216, वरिष्ठ नागरिक 87, स्नैचिंग 76, हत्या 10, लूट 13 और एससी/एसटी से जुड़े 14 मामले शामिल रहे। ये आंकड़े इस बात का प्रमाण हैं कि कुमाऊँ पुलिस सिर्फ़ कॉल नहीं गिन रही, बल्कि हर कॉल के पीछे खड़े इंसान को प्राथमिकता दे रही है।

मैदान से भरोसे के जीवंत उदाहरण

हरियाणा से घूमने आई महिला के साथ 8 दिसंबर 2025 को हुई मारपीट की घटना पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। बाद में पुलिस कंट्रोल रूम से पीड़िता से फीडबैक लिया गया, जिस पर उन्होंने उत्तराखण्ड पुलिस की त्वरित और प्रभावी कार्रवाई पर संतोष जताया। नशे की गिरफ्त में फंसे एक युवक के मामले में पुलिस ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए परिवार की मदद की और युवक को नशा मुक्त कराने की दिशा में प्रयास शुरू किए, जिससे परिवार का भरोसा और मजबूत हुआ। चम्पावत में सड़क दुर्घटना की सूचना पर पुलिस ने घायल को तत्काल रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया और परिजनों को सूचित कर मानवता और कर्तव्य का उदाहरण पेश किया। 11 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म प्रयास के मामले में हाईवे पेट्रोलिंग की सतर्कता से आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया गया, वहीं वरिष्ठ नागरिकों की सहायता में पुलिस ने सूचना मात्र पर अस्पताल पहुंचाकर करुणा का परिचय दिया।

सख़्ती और संवेदनशीलता का संतुलन

आईजी रिद्धिम अग्रवाल के नेतृत्व में यह स्पष्ट संदेश दिया गया है कि आपातकालीन सेवाओं में कोई समझौता नहीं होगा, पीड़ित से संवाद ही पुलिस की असली परीक्षा है और जनता का विश्वास ही पुलिस की सबसे बड़ी ताकत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच और आईजी की ज़मीनी निगरानी ने कुमाऊँ को विश्वास-आधारित पुलिसिंग का मॉडल बना दिया है, जहाँ खाकी अब सिर्फ़ कानून की प्रतीक नहीं, बल्कि सुरक्षा, संवेदना और भरोसे की पहचान बनती जा रही है।

एक नजर

पुलिस विभाग में फेरबदल, दो निरीक्षकों के तत्काल प्रभाव से तबादले

पथ प्रवाह, देहरादून। पुलिस विभाग में प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से निरीक्षक नागरिक पुलिस के स्तर पर तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण एवं नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं। यह स्थानांतरण अधिकारियों के स्वयं के अनुरोध अथवा रिक्त पदों के सापेक्ष किया गया है। जारी आदेशों के अनुसार निरीक्षक प्रदीप पन्त, जो अब तक प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर के पद पर तैनात थे, को स्थानांतरित करते हुए प्रभारी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट शाखा, पुलिस कार्यालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं निरीक्षक हरिओम राज चौहान, जो वर्तमान में प्रभारी एएचटीयू शाखा, पुलिस कार्यालय में तैनात थे, को स्थानांतरित कर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर के पद पर नियुक्त किया गया है। पुलिस विभाग द्वारा जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि यह स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। विभागीय अधिकारियों का मानना है कि इस प्रशासनिक बदलाव से कार्य प्रणाली में और अधिक मजबूती आएगी तथा कानून-व्यवस्था के संचालन में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

प्रदेश में अपर पुलिस अधीक्षक व उप सेनानायकों की नई तैनाती

पथ प्रवाह, देहरादून। उत्तराखण्ड शासन ने जनहित एवं प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रान्तीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के स्थानांतरण एवं तैनाती से संबंधित आदेश जारी किए हैं। गृह अनुभाग-1 द्वारा निर्गत आदेशों के अनुसार ये सभी स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। इस फेरबदल को पुलिस प्रशासन की कार्यक्षमता और व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

जारी आदेश के तहत शाहजहाँ जावेद खान को अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक से पुलिस अधीक्षक, यातायात अपर निदेशालय के पद पर तैनात किया गया है। जोधराम जोशी को अपर पुलिस अधीक्षक, टिहरी से उप सेनानायक, 40वीं वाहिनी पी.ए.सी., हरिद्वार बनाया गया है। राजन सिंह को अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस मुख्यालय से अपर पुलिस अधीक्षक, पी.ए.सी. मुख्यालय तथा कमला बिष्ट को अपर पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी./विजिलेंस, हल्द्वानी से अपर पुलिस अधीक्षक, प्रशिक्षण, पुलिस मुख्यालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

पदोन्नति के फलस्वरूप कई अधिकारियों को नई तैनातियां दी गई हैं। विवेक कुमार को अपर पुलिस अधीक्षक, एस.टी.एफ., नरेन्द्र पन्त को पुलिस अधीक्षक (क्षेत्रीय), अभिसूचना, हल्द्वानी तथा जूही मनराल को अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस मुख्यालय के पद पर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अंकुश मिश्रा को अपर पुलिस अधीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, पूर्णिमा गर्ग को अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक, पुलिस मुख्यालय तथा आशीष भारद्वाज को अपर पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी. मुख्यालय की जिम्मेदारी दी गई है। इसी क्रम में अविनाश वर्मा को अपर पुलिस अधीक्षक, टिहरी, दीपशिखा अग्रवाल को अपर पुलिस अधीक्षक/मुख्य सुरक्षा अधिकारी, मुख्यमंत्री सुरक्षा, शान्तनु पराशर को उप सेनानायक, एस.डी.आर.एफ. तथा अनुषा बडोला को उप सेनानायक, ए.टी.सी., हरिद्वार के पद पर तैनात किया गया है। शासन ने सभी स्थानांतरित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे तत्काल कार्यभार ग्रहण कर इसकी सूचना पुलिस महानिदेशक के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराएं।

उत्तराखण्ड पुलिस में बड़ा फेरबदल, पुलिस उपाधीक्षकों का स्थानांतरण

पथ प्रवाह, देहरादून। उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय ने पुलिस उपाधीक्षकों की तैनाती में बड़ा बदलाव किया है। पुलिस महानिरीक्षक कार्मिक उत्तराखण्ड, डॉ. योगेन्द्र सिंह रावत के निर्देशानुसार, कई पुलिस उपाधीक्षकों को जनहित व रिक्त पदों के अनुरूप तत्काल प्रभाव से नई जिम्मेदारियों के लिए स्थानांतरित किया गया। सूचना के अनुसार वन्दना वर्मा को चम्पावत से देहरादून स्थानांतरित किया गया है, योगेश चन्द अब अभिसूचना मुख्यालय से पुलिस मुख्यालय में तैनात होंगे। ओशिन जोशी को टिहरी गढ़वाल से सीआईडी सेक्टर देहरादून में भेजा गया है। भाष्कर लाल साह सचिवालय/विधानसभा सुरक्षा से देहरादून पदस्थ होंगे। मनोज के. असवाल और बलवन्त सिंह रावत को भी नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। प्रशासनिक आदेश के तहत संबंधित अधिकारी इन्हें तत्काल कार्यमुक्त कर नई तैनाती के बारे में सूचित करेंगे। इस परिवर्तन का उद्देश्य पुलिस कार्य प्रणाली को और प्रभावी बनाना बताया गया है।

योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें अधिकारी : सीडीओ रामजी शरण शर्मा

पथ प्रवाह, अल्मोड़ा

विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी रामजी शरण शर्मा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य बैंकों एवं विभागों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करना तथा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत लंबित प्रकरणों का शीघ्र एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करना रहा।

बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने स्वरोजगार योजना 2.0 के अंतर्गत लंबित मामलों की गहन समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी प्रकरणों का त्वरित समाधान किया जाए, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जा सके। उन्होंने पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं की प्रगति, आवश्यक दस्तावेजों की समय पर पूर्ति तथा दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया।

सीडीओ ने कहा कि ऋण वितरण प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी एवं सुचारु बनाना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) एवं कार्यविधियों के पुनर्परिभाषण, शिकायत निवारण तंत्र को और अधिक मजबूत बनाने तथा मैपिंग से संबंधित समस्याओं के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए

गए। बैठक में खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी पहलों को बढ़ावा देने और इसके माध्यम से स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन की संभावनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

इसके अतिरिक्त शहरी विकास के अंतर्गत संचालित स्वनिधि योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ समय पर और प्रभावी ढंग से पहुंचना चाहिए। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने और योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता एवं समयबद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी ने स्पष्ट किया कि जनकल्याणकारी योजनाओं का वास्तविक उद्देश्य तभी पूर्ण होगा जब उनका लाभ पारदर्शी ढंग से आमजन तक पहुंचे। इसके लिए विभागीय एवं बैंक अधिकारियों को समन्वय बनाकर जिम्मेदारी के साथ कार्य करना होगा।

बैठक में परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास अभिकरण के.एन. तिवारी, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सहित विभिन्न बैंकिंग संस्थानों के प्रतिनिधि, वित्त विभाग, उद्यान विभाग, कृषि विभाग, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), रीप (REAP), आरबीआईसी हवालबाग सहित विभिन्न विभागों एवं संस्थानों के अधिकारी उपस्थित रहे।

रिखणीखाल की कुमाल्डी न्याय पंचायत में बहुउद्देश्यीय शिविर, 205 ग्रामीण लाभान्वित

पथ प्रवाह, पौड़ी गढ़वाल

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में संचालित 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत विकासखंड रिखणीखाल की न्याय पंचायत कुमाल्डी स्थित न्याय पंचायत भवन में एक बहुउद्देश्यीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में स्थानीय विधायक महंत दिलीप रावत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि अपर सचिव, सहकारिता एवं ऊर्जा मेहरबान सिंह बिष्ट विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। शिविर के दौरान विधायक महंत दिलीप रावत ने कहा कि सरकार की यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में जनसमस्याओं के त्वरित समाधान और पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ सीधे पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि ऐसे शिविरों से आम जनता का शासन-प्रशासन पर भरोसा मजबूत होता है। अपर सचिव मेहरबान सिंह बिष्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविर में प्राप्त सभी शिकायतों का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए उनका शीघ्र, पारदर्शी और प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को समय पर राहत मिल सके

और शासन की मंशा धरातल पर दिखाई दे। नोडल अधिकारी एवं सहायक श्रमायुक्त कोटद्वार शैलेश सती ने जानकारी दी कि शिविर में घेरबाड़, सड़क, स्वास्थ्य, विद्युत, पेयजल, वन, गूल मरम्मत सहित विभिन्न विषयों से संबंधित कुल 62 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर संबंधित विभागों को भेजा गया है। उन्होंने बताया कि शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों के माध्यम से लगभग 205 ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। इसके साथ ही 15 ग्रामीणों के विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र बनाए जाने हेतु आवेदन पत्र भरवाए गए। शिविर में कृषि, समाज कल्याण, उद्यान, वन, स्वास्थ्य, आयुर्वेदिक एवं यूनानी, पशुपालन, खाद्य एवं पूर्ति, बाल विकास सहित कुल 23 विभागों ने सहभागिता की और अपने-अपने विभागों की योजनाओं की जानकारी देकर ग्रामीणों को लाभान्वित किया। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख रिखणीखाल रेनू रावत, उप जिलाधिकारी शालिनी मौर्य, खंड विकास अधिकारी देवेश पंत, उप प्रभागीय अधिकारी रजत कपिल, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) सुनील कोटनाला, क्षेत्र पंचायत सदस्य बसंती शाह एवं यशपाल सिंह, ग्राम प्रधान शांति देवी, सुनीता देवी, पूजा देवी, सिन्धु देवी सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

सड़क सुरक्षा माह-2026: उद्योग क्षेत्रों में चला व्यापक जागरूकता अभियान

पथ प्रवाह, लक्सर।

सड़क सुरक्षा माह-2026 के अंतर्गत जनपद हरिद्वार में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने और यातायात नियमों के प्रति आमजन में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से उद्योग क्षेत्रों में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में परिवहन विभाग द्वारा विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में वाहन चालकों, श्रमिकों एवं कर्मचारियों को सड़क सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं।

28 जनवरी 2026 को श्री सीमेंट, लक्सर में सचल दल गोवर्धनपुर द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान परिवहन कर अधिकारी मुकेश भारती ने वाहन चालकों को यातायात नियमों की विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए सुरक्षित ड्राइविंग के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा कि सड़क पर वाहन चलाते समय निर्धारित गति सीमा का पालन, नशे की हालत में वाहन न चलाना तथा यातायात संकेतों का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है, जिससे दुर्घटनाओं में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है। कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न अभियोगों की जानकारी देते हुए गुड सेमिरिटन कानून एवं गोल्डन आवर की अहमियत पर विशेष प्रकाश डाला गया। अधिकारियों ने बताया कि किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित को तत्काल और सुरक्षित सहायता पहुंचाना कानूनन सुरक्षित है और इससे अनमोल जीवन बचाया जा सकता है। वाहन चालकों से अपील की गई कि वे हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य प्रयोग, ओवरलोडिंग से परहेज, तेज गति से वाहन न चलाने तथा शराब पीकर वाहन न चलाने जैसे नियमों का सख्ती से पालन करें। इस अवसर पर परिवहन कर अधिकारी रविंद्र पाल सैनी, प्रवर्तन कार्मिक अनिल, मीनाक्षी, हरेंद्र, जसपाल एवं सौरभ उपस्थित रहे।

वहीं 29 जनवरी 2026 को इंडस्ट्रियल एरिया रायपुर, भगवानपुर स्थित एवरेस्ट फैक्टरी में भी सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व एआरटीओ प्रवर्तन कृष्ण चंद्र पलड़िया ने किया। उन्होंने उद्योग में कार्यरत चालकों एवं कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि थोड़ी सी सावधानी और नियमों के पालन से कई बहुमूल्य जानें बचाई जा सकती हैं।

उन्होंने सड़क सुरक्षा को केवल कानून नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी बताते हुए सभी से सुरक्षित यातायात व्यवहार अपनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों ने सड़क सुरक्षा नियमों के पालन का संकल्प लिया।

इस दौरान राकेश थपलियाल (टीएसआई), टीएआई सोनू एवं टीसी शोएब सहित प्रवर्तन टीम के सदस्य मौजूद रहे।

किसानों के हितों की अनदेखी तो उग्र आंदोलन की चेतावनी, 6 सूत्रीय मांगों को जोरदार प्रदर्शन

पथ प्रवाह, लक्सर।

किसानों एवं मजदूरों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन (क्रांति) अराजनीतिक ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आंदोलन का ऐलान कर दिया है। संगठन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को संबोधित छह सूत्रीय मांगपत्र जिलाधिकारी हरिद्वार के माध्यम से सौंपते हुए स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि मांगों का शीघ्र समाधान नहीं हुआ, तो हजारों किसान देहरादून कूच कर मुख्यमंत्री आवास पर आंदोलन करेंगे।

गुरुवार को संगठन से जुड़े सैकड़ों किसान और मजदूर लक्सर के शिव चौक पर एकत्र हुए, जहां सरकार और प्रशासन के खिलाफ जोरदार धरना-प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने जमकर नारेबाजी करते हुए अपनी समस्याओं को मुखरता से उठाया। इसके पश्चात सभी किसान जुलूस की शक्ल में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। किसानों की प्रमुख मांगों में टोल प्लाजा पर कैमरों के माध्यम से किए जा रहे चालानों में राहत, खनन मामलों में अधिकारियों की कथित मनमानी पर कार्रवाई, जबरन स्मार्ट मीटर लगाए जाने पर रोक, दिहाड़ी मजदूरों पर लगाए जा रहे भारी चालानों में कमी, पथरी नदी को नमामि गंगे योजना से जोड़ना, तथा गन्ना किसानों पर लागू 15 किलोमीटर की बाध्यता समाप्त करना शामिल है। इस मौके पर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास चौधरी ने कहा कि किसान और मजदूर पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे में चालान और जुर्मानों का अतिरिक्त बोझ डालना पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकार को जमीनी हकीकत समझते हुए किसानों को राहत देनी चाहिए। वहीं प्रदेश अध्यक्ष युनुस अहमद ने प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना हो रही है, तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

जिला अध्यक्ष अनिल चौधरी ने दो टूक चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने किसानों की समस्याओं पर शीघ्र ठोस निर्णय नहीं लिया, तो संगठन प्रदेशभर से किसानों को एकजुट कर देहरादून में बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने भगत दा को दी पद्म भूषण सम्मान की बधाई

पथ प्रवाह, देहरादून।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से उनके डिफेंस कॉलोनी, देहरादून स्थित आवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने श्री कोश्यारी को देश के प्रतिष्ठित पद्म भूषण सम्मान हेतु चयनित किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि यह सम्मान उत्तराखंड के गौरव भगत सिंह कोश्यारी के दीर्घकालिक, समर्पित और राष्ट्रसेवा से परिपूर्ण सार्वजनिक जीवन का उचित एवं गौरवपूर्ण सम्मान है। उन्होंने कहा कि श्री कोश्यारी ने उत्तराखंड आंदोलन से लेकर राज्य के गठन, प्रशासनिक नेतृत्व तथा संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन तक हर भूमिका में प्रदेश और देश को सशक्त दिशा प्रदान की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भगत सिंह कोश्यारी का जीवन जनसेवा, सादगी और राष्ट्रनिष्ठा का जीवंत उदाहरण है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत रहेगा। उन्होंने कहा कि पद्म भूषण सम्मान से न केवल उत्तराखंड, बल्कि सम्पूर्ण देश स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री धामी ने ईश्वर से श्री भगत सिंह कोश्यारी के उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन की कामना भी की।

वन माफिया की साजिश नाकाम, नदी में छुपाई शीशम लकड़ी से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त

पथ प्रवाह, लक्सर।

खानपुर क्षेत्र में वन संपदा की अवैध लूट को अंजाम देने की कोशिश कर रहे वन माफिया की एक बड़ी साजिश को लक्सर वन विभाग ने समय रहते नाकाम कर दिया। गांव शेरपुर बेला से बिना अनुमति काटी गई शीशम की बेशकीमती लकड़ी से लदी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को वन विभाग की टीम ने जब्त कर लिया, जबकि लकड़ी तस्कर मौके से फरार होने में सफल हो गए।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिलने पर लक्सर वन क्षेत्राधिकारी महेंद्र गिरी के नेतृत्व में वन विभाग की एक विशेष टीम गठित कर खानपुर क्षेत्र में घेराबंदी की गई। जैसे ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, तस्करों में हड़कंप मच गया। खुद को घिरता देख तस्करों ने शीशम की लकड़ी से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली को जंगल से सटे नदी के पास एक खेत में छुपा दिया और अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। वन विभाग की टीम ने जान जोखिम में डालते हुए कड़ी मशक्कत के बाद नदी से ट्रैक्टर-ट्रॉली को बाहर निकाला। ट्रॉली में बड़ी मात्रा में शीशम की लकड़ी भरी हुई पाई गई। जब्त ट्रैक्टर-ट्रॉली को तत्काल लक्सर वन विभाग कार्यालय लाया गया, जहां अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में वन क्षेत्राधिकारी महेंद्र गिरी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि शीशम की यह लकड़ी किसी किसान के खेत से अवैध रूप से काटी गई, जिसके लिए न तो कोई वैध अनुमति ली गई थी और न ही वन विभाग को कोई सूचना दी गई थी। उन्होंने बताया कि मामले में अज्ञात लकड़ी तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही ट्रैक्टर-ट्रॉली के माध्यम से ट्रैक्टर स्वामी की पहचान की जा रही है, जिसके बाद उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

वन विभाग ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि वन संपदा की लूट किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवैध कटान और लकड़ी तस्करी में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई से क्षेत्र में सक्रिय वन माफिया में हड़कंप मचा हुआ है।

राशन डीलर का तांडव: जांच को पहुँची पूर्ति निरीक्षक से हाथापाई

पथ प्रवाह, लक्सर। ग्रामीणों को राशन न देकर केवल पर्ची थमाने और ई-केवाईसी के नाम पर अवैध वसूली की शिकायतों की जांच करने पहुँची खाद्य पूर्ति निरीक्षक के साथ महिला राशन डीलर ने हाथापाई और दबाव बनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यह घटना लक्सर क्षेत्र की है, जिसने पूरे इलाके में प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, लक्सर गांव की राशन डीलर सुषमा के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि वह उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा में राशन नहीं देती, बल्कि उन्हें केवल एक पर्ची थमा दी जाती है और राशन रजिस्टर पर अंगूठा या हस्ताक्षर करवा लिए जाते हैं। इसके साथ ही ई-केवाईसी के नाम पर प्रति राशन कार्ड 10 की अवैध वसूली किए जाने के भी गंभीर आरोप लगाए गए थे। शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए खाद्य पूर्ति निरीक्षक बबीता जांच के लिए लक्सर गांव स्थित राशन की दुकान पर पहुँचीं। आरोप है कि निरीक्षक को अकेला देखकर राशन डीलर ने अपने समर्थकों को मौके पर बुला लिया और उन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। इसी दौरान निरीक्षक और राशन डीलर के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जो देखते ही देखते हाथापाई में तब्दील हो गई। स्थिति बिगड़ती देख खाद्य पूर्ति निरीक्षक ने तत्काल राशन की दुकान पर ताला लगवा दिया और मौके से लौटना पड़ा। घटना के दौरान कुछ मीडिया कर्मी भी मौके पर पहुँच गए, जिन्होंने पूरे घटनाक्रम का वीडियो रिकॉर्ड किया, जो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। खाद्य पूर्ति निरीक्षक बबीता ने बताया कि आरोपी राशन डीलर सुषमा के पास मिर्जापुर शादात गांव की दुकान के साथ-साथ लक्सर गांव, बसेड़ी और सैठपुरा की राशन दुकानें भी अटैच हैं। जांच में प्रथम दृष्टया यह तथ्य सामने आया है कि ग्रामीणों को राशन न देकर केवल पर्ची दी जा रही थी और रजिस्टर पर उनके हस्ताक्षर व अंगूठे लगवाए जा रहे थे। घटना के दौरान राशन डीलर ने बौखलाहट में खाद्य पूर्ति निरीक्षक पर 50 हजार की रिश्वत मांगने और कमीशनखोरी जैसे गंभीर आरोप भी लगाए। हालांकि पूर्ति निरीक्षक ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार और बेबुनियाद बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया है। खाद्य पूर्ति निरीक्षक बबीता ने स्पष्ट किया कि पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी जा रही है और जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने रिवर प्रोटेक्शन व डीसिल्टिंग कार्यों की प्रगति की समीक्षा

पथ प्रवाह, देहरादून

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत चल रहे रिवर प्रोटेक्शन कार्यों एवं डीसिल्टिंग की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आगामी मानसून सीजन को देखते हुए बाढ़ की संभावनाओं से निपटने के लिए सभी कार्य समयबद्ध ढंग से पूर्ण किए जाएं, ताकि जनधन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

बैठक में अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि लघु सिंचाई विभाग द्वारा राज्य में जल संरक्षण, संवर्द्धन एवं संभरण योजनाओं के तहत विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत चेक डैम निर्माण, रिचार्ज शाफ्ट निर्माण एवं तालाबों के निर्माण का कार्य तेजी

से प्रगति पर है। विभाग द्वारा प्रदेशभर में अब तक 708 चेक डैम का निर्माण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त ऊधम सिंह नगर, नैनीताल एवं हरिद्वार जनपदों में कुल 419 रिचार्ज शाफ्ट स्थापित किए गए हैं, जिनसे प्रतिवर्ष लगभग 108.94 करोड़ लीटर भूजल का रिचार्ज संभव हो सकेगा।

अधिकारियों ने यह भी जानकारी दी कि 09 वन प्रभागों में पेयजल विभाग एवं सारा (स्क्रू) के माध्यम से 14 जल स्रोतों के उपचार हेतु जल संरक्षण से संबंधित कार्य किए जा रहे हैं। वहीं कैम्पा योजना के अंतर्गत विभिन्न वन प्रभागों में 247 जल धाराओं के उपचार का कार्य संचालित किया जा रहा है, जिससे जल स्रोतों के संरक्षण के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जल उपलब्धता को भी मजबूती मिलेगी।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने वनाग्नि की रोकथाम को लेकर भी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी गर्मी और शुष्क मौसम को देखते हुए वन विभाग अभी से पूरी तैयारी सुनिश्चित करे। वनाग्नि की रोकथाम के लिए पर्याप्त मानव संसाधन के साथ-साथ आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता समय रहते सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने यह भी निर्देश दिए कि वन पंचायतों एवं वन क्षेत्रों के आस-पास रहने वाले स्थानीय लोगों के साथ विभाग नियमित समन्वय बनाए रखे। वन संरक्षण के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही फायर लाइन की समय पर सफाई, वनभूमि पर हो रहे अतिक्रमण को प्राथमिकता के आधार पर हटाने के भी निर्देश दिए गए।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव शैलेश बगोली, युगल किशोर पंत सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

एक नजर

बागेश्वर को सम्मान, तीन मोटर मार्गों के नाम शहीदों व स्वतंत्रता सेनानियों के नाम

पथ प्रवाह, देहरादून(मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद बागेश्वर के तीन प्रमुख मोटर मार्गों के नाम परिवर्तन किए जाने का अनुमोदन प्रदान कर दिया है। यह निर्णय क्षेत्र की ऐतिहासिक विरासत, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों के सम्मान को चिरस्थायी स्वरूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। प्रस्तावों के अनुसार जनपद बागेश्वर में काण्डे-थपलिया मोटर मार्ग का नाम अब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय राम सिंह गडिया मोटर मार्ग किया जाएगा। वहीं करूली बैण्ड से गाजली बिजौरिया मोटर मार्ग को शहीद स्वर्गीय रामदत्त पाण्डेय मोटर मार्ग के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ ही बिलखेत-गैराड़ मोटर मार्ग (कलनाबैण्ड-पंतक्वैराली मोटर मार्ग) का नाम परिवर्तन कर स्वर्गीय श्री हीरा सिंह धपोला मोटर मार्ग किए जाने को भी मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस अनुमोदन से क्षेत्रीय जनभावनाओं को सम्मान मिला है। स्थानीय लोगों का मानना है कि सड़कों के नाम महापुरुषों और शहीदों के नाम पर रखे जाने से नई पीढ़ी को उनके बलिदान और योगदान से प्रेरणा मिलेगी तथा क्षेत्र की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान और अधिक सशक्त होगी। शासन स्तर पर नाम परिवर्तन की प्रक्रिया को औपचारिक रूप से पूर्ण करते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाने की तैयारी की जा रही है।

गोमांस की तस्करी के आरोप में महिला समेत दो गिरफ्तार

पथ प्रवाह, हरिद्वार। बहादरबाद पुलिस ने गोमांस की तस्करी के आरोप में एक महिला समेत दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से प्रतिबंधित गोमांस भी बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक चौकी प्रभारी शान्तरशाह को ग्राम मरगूबपुर में महिला के घेर में गोकशी किये जाने की सूचना प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना पर तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस टीम द्वारा आरोपी के घेर में दबिश दी गई तो घेर से करीब 50 किग्रा संदिग्ध गोमांस बरामद हुआ। गोकशी में आलीम पुत्र अब्दुला, शमीम पुत्र अख्तर, मुस्तकीम पुत्र यामीन एवं शेर आलम पुत्र शब्बीर का सम्मिलित होना पाया गया। आरोपी महिला को मौके पर महिला होमगार्ड की मौजूदगी में हिरासत में लिया गया। मौके पर पशु चिकित्साधिकारी को बुलाया गया जिनके द्वारा प्रथम दृष्टता बरामदा मांस गौ वंशीय पशु का पाये जाने पर परीक्षण हेतु मांस का नमूना लिया गया। बरामद गौमांस को नजदीक खाली स्थान पर अम्लीय छिडकाव कर नष्ट किया गया। गोकशी की घटना में सम्मिलित सह आरोपी शेर मोहम्मद को दबिश देकर उसके मकान से हिरासत में लिया गया।

हरिद्वार पुलिस का नशा तस्करों पर कार्रवाई, एक गिरफ्तार

पथ प्रवाह, हरिद्वार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार नशा तस्करों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रभारी निरीक्षक कोतवाली रानीपुर के नेतृत्व में रानीपुर पुलिस द्वारा लगातार नशा तस्करों के विरूद्ध ताबडतोड कार्यवाही की जा रही है। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली रानीपुर के नेतृत्व में पुलिस टीमों द्वारा नशा तस्करों के विरूद्ध ताबडतोड कार्यवाही का सिलसिला जारी रखते हुए नशा तस्करों के विरूद्ध छापेमारी एवं चैकिंग अभियान चलाकर पुलिस टीम द्वारा सुमननगर क्षेत्रान्तर्गत रोह नदी रपटा नदी पुल के पास से एक आरोपी सुभाष कुमार पुत्र उमेश भगत निवासी रामधाम थाना रानीपुर हरिद्वार मूल पता गांव कुढनी थाना कुढनी जिला मुज्जफरपुर बिहार को एक अपाची मोटर साइकिल सहित धर दबोचा। आरोपी के कब्जे से 5.77 ग्राम अवैध स्मैक (कीमती लगभग 55,000/- रू0)की बरामद की गई। उसकी मोटर साइकिल को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि यह स्मैक रावली महदूद सिडकुल के रहने वाले पंकज से ली थी, जो पहले भी स्मैक में जेल गया था। रानीपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपी सुभाष कुमार व प्रकाश में आये आरोपी पंकज नि0 रावली महदूद सिडकुल हरिद्वार के विरूद्ध थाने पर एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री हरदा से की शिष्टाचार भेंट

पथ प्रवाह, देहरादून।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत से उनके डिफेंस कॉलोनी, देहरादून स्थित आवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने श्री रावत का कुशलक्षेम जाना तथा उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना की।

भेंट के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने आत्मीयता और सादगी का परिचय देते हुए अपने खेत में उत्पादित चावल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को भेंट किए। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि यह भेंट केवल एक औपचारिक उपहार नहीं, बल्कि उत्तराखंड की कृषि परंपरा, किसानों की मेहनत और स्थानीय उत्पादों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य की पहचान उसकी मिट्टी, किसान और परिश्रम से जुड़े मूल्यों में निहित है।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की इस पहल को राजनीतिक शिष्टाचार और आपसी सम्मान की

मिसाल के रूप में देखा जा रहा है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर की गई यह भेंट प्रदेश में सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण राजनीतिक संस्कृति को दर्शाती है।

पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्नेहिल व्यवहार और आत्मीय भेंट के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा अपने खेत में उत्पादित चावल भेंट करना एक भावनात्मक और सांस्कृतिक संदेश है, जो राजनीति में आपसी सद्भाव, सम्मान और मर्यादा को मजबूत करता है।

गुरु तेगबहादुर इण्टर कालेज में आयोजित किया जागरुकता कार्यक्रम

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

जनपद हरिद्वार पुलिस द्वारा चलाए जा रहे जागरुकता अभियान 'पुलिस आपके द्वार' कार्यक्रम के तह?त एसएसपी के निर्देश पर बुग्गावाला पुलिस टीम द्वारा गुरु तेगबहादुर इण्टर कालेज में जागरूकत अभियान चलाया गया।

अभियान के दौरान महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा से संबंधित विभिन्न कानूनों, आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112, महिला हेल्पलाइन 1090/1091 साइबर अपराध से बचाव, छेड़छाड़, घरेलू हिंसा तथा किसी भी आपात स्थिति में त्वरित सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित महिलाओं एवं बालिकाओं को यह भी बताया गया कि किसी भी प्रकार की समस्या

होने पर वे बिना संकोच पुलिस से संपर्क करें। पुलिस सदैव उनकी सहायता एवं सुरक्षा के लिए तत्पर है। साथ ही आत्मरक्षा के सामान्य उपायों एवं सतर्कता संबंधी महत्वपूर्ण सुझाव भी साझा किए गए। स्थानीय नागरिकों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे समाज में सुरक्षा एवं विश्वास बढ़ाने वाला कदम बताया की पुलिस द्वारा भविष्य में भी इस प्रकार के जनजागरूकता कार्यक्रम निरंतर आयोजित किए जाने की बात कही गई।

अफसर बिटिया कार्यक्रम में छात्राओं को अधिकार, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता का संदेश

पथ प्रवाह, पौड़ी गढ़वाल

विकासखंड पाबौ के राजकीय इंटर कॉलेज चोलोसैंण में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत 'अफसर बिटिया' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बाल विकास परियोजना अधिकारी चन्द्रकांता काला ने की। इस अवसर पर योजना के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए गिरते लिंगानुपात, भ्रूण हत्या की रोकथाम तथा बालिकाओं को शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया गया।

कार्यक्रम में वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) की केंद्र प्रशासिका लक्ष्मी रावत ने बालक-बालिकाओं को उनके अधिकारों, पॉक्सो एक्ट, बाल विवाह प्रतिषेध कानून सहित अन्य कानूनी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी। वहीं सीएचसी पाबौ की चिकित्सा अधिकारी डॉ. नेहा ने किशोरियों को मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता, पोषण, स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों एवं व्यक्तिगत देखभाल के विषय में उपयोगी जानकारी दी।

विद्यालय के प्रवक्ता भगवती प्रसाद ने बालिकाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने में शिक्षा की भूमिका पर बल दिया, जबकि प्रवक्ता

शशि शेखर ममगाईं ने कहा कि माता-पिता बच्चों के सबसे अच्छे मित्र होते हैं, इसलिए किसी भी समस्या को उनसे अथवा शिक्षकों से साझा करना चाहिए। कार्यक्रम के अंतर्गत 'मेरे सपने, मेरी उड़ान' विषय पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें वर्षा, अर्चना एवं अंकिता को प्रथम, तनीषा, रितिका एवं श्रेया भंडारी को द्वितीय तथा करिश्मा, रितिका एवं राधिका को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं, छात्राएं एवं संबंधित विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

स्वामी/प्रकाशक वीरेन्द्र सिंह ने मुद्रक प्रमोद कुमार, जय माँ गंगा प्रिन्टर्स, राजराणा कॉम्पलैक्स निकट खाद गोदाम, जमालपुर कलां, ज्वालापुर, हरिद्वार (उत्तराखण्ड) से मुद्रित कराकर, मुख्य कार्यालयः 40 शांतिपुरम कॉलोनी जगजीतपुर, कनखल, हरिद्वार, उत्तराखंड 249408 (उत्तराखण्ड) से प्रकाशित किया। वीरेन्द्र सिंह (सम्पादक) 9411111733, डॉ सुशील शर्मा(उप संपादक) 9837906777 किसी भी वाद विवाद का निपटारा हरिद्वार में होगा। वेबसाईट- www.pathpravah.com